घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 181- रविवार 03 - मई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

देशभर में करोड़ों मोबाइल पर एकसाथ अलर्ट मैसेज आया

सायरन की आवाज सुनाई दी,सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की

नई दिल्ली,02 मई 2026। देशभर में शनिवार सुबह 11:45 बजे कई मोबाइल फोन पर एकसाथ सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। स्क्रीन पर हिंदी-अंग्रेजी में एक मैसेज था। सायरन बंद हुआ तो मोबाइल पर मैसेज पढ़कर भी सुनाया गया। इससे कई लोग परेशान हुए,तो कई कन्फ्यूज। यह मैसेज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी NDMA ने भेजा था। NDMA ने इमरजेंसी में लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए 2 मई को सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया।

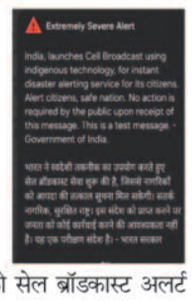

देशभर में इमरजेंसी मैसेज की एकसाथ टेस्टिंग

शनिवार को देश के सभी राज्यों की राजधानियों और दिल्ली-NCR में सभी मोबाइल फोन पर एकसाथ टेस्टिंग मैसेज भेजा गया। यह मैसेज हिंदी और अंग्रेजी के साथ सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी भेजा गया। मैसेज में बताया गया कि यह केवल परीक्षण है और इस पर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है।

सरकार ने पहले ही बताया था...मैसेज से घबराएं नहीं

सरकार ने दो दिन पहले ही मैसेज भेजकर लोगों से अपील की थी कि इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट ट्रायल के दौरान यानी टेस्टिंग वाला मैसेज मिलने पर घबराएं नहीं। शनिवार का मैसेज केवल इमरजेंसी के हालात में चेतावनी देने वाले सिस्टम की जांच के लिए भेजा गया था।

गुजरात हाई कोर्ट ने रेप पीड़िता को 22 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दी

अहमदाबाद,02 मई 2026। नाबालिग रेप पीड़ितों के अधिकारों और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक अहम फैसले में, गुजरात हाई कोर्ट ने 16 साल की एक नाबालिग को अपना 22 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है। 16 साल की एक लड़की ने रेप की वजह से अपनी प्रेग्नेंसी खत्म करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ वटवा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट ने अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल को मेडिकल जांच करने और एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। कोर्ट में जमा की गई मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्भपात में आम तौर पर होने वाले जोखिमों के बावजूद,मेडिकल तौर पर गर्भपात संभव है। इसी आधार पर, हाई कोर्ट ने नाबालिग को गर्भपात करवाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने एक अहम निर्देश देते हुए कहा कि गर्भपात करने से पहले नाबालिग की सहमति लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही, भ्रूण का डीएनए सैंपल जांच अधिकारी को सौंपना होगा,ताकि अपराध की जांच में मदद मिल सके। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर गर्भपात के दौरान बच्चा जिंदा पैदा होता है,तो उसे पूरा इलाज और देखभाल दी जाएगी। अगर नाबालिग बच्चे को नहीं रखना चाहती है,तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।मामले में, याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील झलक सुथार ने कोर्ट के सामने दलील दी कि नाबालिग की मानसिक और शारीरिक हालत को देखते हुए गर्भपात की इजाजत देना बेहद जरूरी है. उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को पीड़िता के हित में अहम बताया।

तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज होने पर भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

नई दिल्ली,02 मई 2026। उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की याचिका को खारिज करते हुए चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के संवैधानिक हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अदालत के इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने स्वागत किया है और टीएमसी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि जिस प्रकार तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल और निराधार आरोपों को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, वह उसकी'बौखलाहट और छटपटाहट' को दर्शाता है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जैसे-जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव आगे बढ़ा, वैसे-वैसे टीएमसी का जनसमर्थन और मनोबल लगातार गिरता गया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और हिंसा-मुक्त मतदान संपन्न होने के बाद पार्टी में बेचैनी और अस्थिरता और बढ़ गई,जबकि एग्जिट पोल के रुझानों ने स्थिति को और स्पष्ट कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि इसके बाद टीएमसी ने बिना आधार वाले मुद्दों को उठाकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जो उनकी राजनीतिक हताशा का संकेत है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले 10 से 12 वर्षों में टीएमसी ने न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर 80 से अधिक बार अपील की है,लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी।

पश्चिम बंगाल पुनर्मतदान : 15 बूथो पर 86 प्रतिशत मतदान,फलता में प्रदर्शन

कोलकाता,02 मई 2026। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में शनिवार को डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के चार और मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों पर पुनर्मतदान शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। शनिवार को हुए पुनर्मतदान में शाम 5 बजे तक 86.90 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज हुआ। दो चरणों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 15 बूथों पर पुनर्मतदान कराया गया। इनमें शाम पांच बजे तक मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 86.11 प्रतिशत और डायमंड हार्बर के चार बूथ पर 87.60 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ। सुबह 9 बजे तक डायमंड हार्बर में 15.83 और मगराहाट पश्चिम में 16.88 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसके अलावा सुबह 11 बजे तक डायमंड हार्बर में 35.92 और मगराहाट पश्चिम में 38.2 प्रतिशत,दोपहर एक बजे तक डायमंड हार्बर में 54.9 प्रतिशत और मगराहाट पश्चिम में 54.9 प्रतिशत और दोपहर 3 बजे तक 72.43 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि, विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के दौरान मिली गड़बड़ियों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने दो विधानसभा क्षेत्र के 15 बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। जिन बूथों पर मतदान हुआ उनमें मगराहाट पश्चिम के बूथ संख्या 46, 126, 127, 128, 142, 214, 215, 216, 230, 231 एवं 232 तथा डायमंड हार्बर के बूथ संख्या 117, 179, 194 और 243 शामिल हैं। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस बीच, फलता में सैकड़ों ग्रामीणों ने मतगणना के बाद सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

ममता बनर्जी का बड़ा दावा : बोलीं... 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी टीएमसी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक दो दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। शनिवार को ममता बनर्जी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के काउंटिंग एजेंटों के साथ एक अहम वर्चुअल बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 200 से अधिक सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने मतगणना केंद्र पर तैनात होने वाले काउंटिंग एजेंटों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन सभी एजेंट केंद्रों पर नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज कराएं। साथ ही, वे मतगणना की पल-पल की जानकारी पार्टी नेतृत्व को देते रहें। ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक मतगणना की पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, तब तक कोई भी एजेंट केंद्र छोड़कर बाहर न आए। मुख्यमंत्री ने हालिया एग्जिट पोल्स को पूरी तरह से नकार दिया। कई एग्जिट पोल्स में भाजपा को बढ़त दिखाई गई है। इस पर ममता ने कहा कि ये सब शेयर बाजार को प्रभावित करने की साजिश है। उन्होंने इसे 2021 और 2024 के चुनाव जैसा ही प्रोपेगेंडा बताया। सीएम दीदी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं पर बर्बरता की है। उन्होंने वादा किया कि संकट के समय पार्टी के साथ खड़े रहने वाले कार्यकर्ताओं को भविष्य में पुरस्कृत किया जाएगा।

धनबाद-कोयला खदान में स्लरी ढहने से 4 मजदूरों की मौत

कोल वाशरी में स्लरी लोडिंग कर रहे थे

धनबाद,02 मई 2026। झारखंड के धनबाद में शनिवार को कोयला स्लरी (कोयले का पाउडर) धंस गई, जिससे 4 मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी मजदूर मुनीडीह में बीसीसीएल की कोल वाशरी में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मलबा गिर गया। आसपास के मजदूरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव काम शुरू किया और प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। मलबा हटाकर चारों मजदूरों के शव बाहर निकाले गए। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मृतक की पहचान प्रेम बाउरी, माणिक बाउरी, दीपक बाउरी और नारायण यादव के रूप में की गई है। घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, इस हादसे ने एक बार फिर खनन क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजन ने बीसीसीएल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

संदीप पाठक पर पंजाब में दो एफआईआर,भाजपा ने सरकार पर लगाया बदले की कार्रवाई का आरोप

नई दिल्ली,02 मई 2026। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भाजपा ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताते हुए पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पहले से ही खराब है और पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक कार्रवाई के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने संदीप पाठक के आवास पर छापेमारी की कोशिश भी की, जो गलत है। भाजपा ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया और सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

जज ने किया सुसाइड,मचा हड़कंप

नई दिल्ली,02 मई 2026। दिल्ली के सफदरजंग इलाके से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। न्यायिक सेवा से जुड़े जज अमन कुमार शर्मा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, 35 वर्षीय अमन कुमार शर्मा को लेकर उनके भाई ने दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर सूचना दी कि 'मेरे भाई ने घर के बाथरूम में आत्महत्या कर ली है।' सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जज अमन कुमार शर्मा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उन्होंने फंदे से लटककर जान दी। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

एलपीजी सिलेंडरों की सौ फीसदी सप्लाई की जा रही सुनिश्चित,आपूर्ति ठप्प होने की कोई रिपोर्ट नहीं : केंद्र सरकार

नई दिल्ली,02 मई 2026। केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर सिलेंडर खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। घरेलू परिवारों को एलपीजी सिलेंडरों की 100 फीसदी सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। विदेश मंत्रालय खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में चल रहे घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि कल ऑनलाइन घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की बुकिंग बढ़कर 99 फीसदी हो गई, जबकि ओटीपी आधारित डिलीवरी 94 फीसदी से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि मार्च, 2026 से अब तक लगभग 5.96 लाख पीएनजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं और 2.68 लाख अतिरिक्त कनेक्शनों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, इसके साथ ही लगभग 6.66 लाख ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है।

टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा... केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती नियमों के खिलाफ नहीं

नई दिल्ली,02 मई 2026। पश्चिम बंगाल में मतगणना के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने कहा कि काउंटिंग टेबल पर केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती नियमों के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने कहा, अगर मतगणना पर्यवेक्षकों और सहायकों को पूरी तरह से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से भी लिया जाता है,तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। कानून चुनाव आयोग के ढांचे के तहत राज्य या केंद्र के अधिकारियों में से चयन की अनुमति देता है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई बिना कोई आदेश पारित किए खत्म कर दी। कोर्ट ने केवल चुनाव आयोग की इस बात को दर्ज किया कि मतगणना कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी परिपत्र का अक्षरशः पालन किया जाएगा। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने कहा था कि अब वह केवल यह मांग कर रही है कि परिपत्र के अनुसार हर मतगणना केंद्र पर कम से कम एक व्यक्ति राज्य सरकार का कर्मचारी हो। टीएमसी का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, पहले से ही केंद्र सरकार का एक नामित सदस्य मौजूद है और अब एक और सदस्य जोड़ा जा रहा है। सर्कुलर में राज्य सरकार के नामित सदस्य की जरूरत बताई गई है लेकिन नियुक्ति नहीं की जा रही। अनुच्छेद 324 का मतलब यह नहीं है कि चुनाव आयोग जो मन मे आए करे। ऐसी चीजें पहले नहीं हुईं। चुनाव आयोग को कहां से आशंका हो गई? सिब्बल ने कहा, 4 मुद्दे हैं। पहला-डीईओ को नोटिस 13 अप्रैल को जारी किया गया, लेकिन हमें जानकारी 29 अप्रैल को मिली। दूसरा-हमें आशंका है कि हर बूथ में गड़बड़ी होने वाली है। तीसरा ये कि हर बैठक में पहले ही एक केंद्रीय अधिकारी मौजूद है, तो अब एक और अधिकारी की क्या जरूरत है? चौथा यह कि परिपत्र में ही कहा गया है कि एक राज्य अधिकारी भी होना चाहिए, लेकिन वे नियुक्त नहीं करते हैं। कोर्ट ने कहा, मतगणना के लिए तैनात सभी कर्मी चुनाव आयोग के नियंत्रण में हैं, इसलिए यह मायने नहीं रखता कि वे केंद्र से हैं या राज्य से। पार्टियों से परामर्श करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव और मतगणना एजेंट मौजूद रहेंगे और प्रत्येक मतगणना केंद्र पर 3 कर्मी होंगे। सरकारी कर्मचारियों से किसी तरह की निष्ठा की अपेक्षा नहीं की जा सकती और वे आधिकारिक कर्तव्य के तहत काम करते हैं। दरअसल,चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि हर काउंटिंग टेबल पर कम से कम एक सुपरवाइजर या असिस्टेंट केंद्रीय सरकार या पीएसयू का कर्मचारी होना चाहिए। टीएमसी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि यह बिना पर्याप्त अधिकार के लिया गया है और दूसरे राज्यों में ऐसा नियम लागू नहीं किया गया। इस मामले में पहले टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था,जहां हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला सुनाया था।

पश्चिम बंगाल में मतगणना के लिए 165 काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त

कोलकाता,02 मई 2026। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था को और सख्त करते हुए अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। आयोग ने कुल 242 पर्यवेक्षकों को तैनात किया है, जिनमें 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस पर्यवेक्षक शामिल हैं। दो चरणों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार, अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वरों को उन विधानसभा क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा जहां एक से अधिक मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। इनका काम पहले से नियुक्त पर्यवेक्षकों की सहायता करना और मतगणना प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित कराना होगा। इसके अलावा प्रत्येक मतगणना केंद्र के लिए एक-एक पुलिस पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है। इनका दायित्व मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की निगरानी करना होगा। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्हें अन्य चुनाव अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करना होगा। आयोग ने यह भी याद दिलाया है कि काउंटिंग ऑब्जर्वर और रिटर्निंग ऑफिसर को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को मोबाइल फोन के साथ मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

देश को जल्द मिलेंगी हाइपरसोनिक मिसाइलें

सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से दोगुनी होगी रफ्तार,कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा

नई दिल्ली,02 मई 2026। भारत ने युद्धों की बदलती रणनीति को देखते हुए अत्याधुनिक 'हाइपरसोनिक' मिसाइल तकनीक पर काम तेज कर दिया है। डीआरडीओ प्रमुख समीर वी.कामत ने एक कार्यक्रम में बताया है कि देश जल्द'हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल' और'हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल' से लैस होगा। इनकी रफ्तार सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से दोगुनी होगी। इसकी खासियतों की वजह से दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं पाएगा। डीआरडीओ प्रमुख के अनुसार, ग्लाइड मिसाइल का पहला परीक्षण जल्द संभव है। स्क्रैमजेट इंजन पर आधारित क्रूज मिसाइल को लेकर भी बड़ी कामयाबी मिली है। हाल ही में स्क्रैमजेट प्रोपल्शन का 1,000 सेकंड से ज्यादा समय तक परीक्षण सफल रहा है। औपचारिक मंजूरी मिलने के 5 साल में इस मिसाइल प्रणाली को सेना के बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य है। भारत एंटी-शिप मिसाइल भी विकसित कर रहा है। यह मिसाइल ब्रह्मोस की तुलना में और ज्यादा तेज होगी। इसके तीसरे चरण का परीक्षण इसी महीने किया जाना है।

चीन-रूस इस तकनीक में आगे : रूस के पास 'जिरकॉन' और 'किंजल' हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। चीन के पास 'डीएफ-जेडएफ' है, जो तैनात की जा चुकी हैं। वहीं,अमेरिका इस तकनीक में थोड़ा पीछे रह गया है। अमेरिका के पास टॉमहॉक तकनीक की 'सुपरसोनिक' मिसाइलें हैं। लेकिन हाल के सालों में हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स जैसे एजीएम-183 एआरआरडब्ल्यू असफल रहे हैं।

अग्नि-6: सरकार की हरी झंडी मिलते ही काम शुरू

डीआरडीओ प्रमुख ने स्पष्ट किया कि अग्नि-6 मिसाइल कार्यक्रम के लिए तकनीकी रूप से टीम पूरी तरह तैयार है। जैसे ही सरकार से हरी झंडी मिलेगी, हम इस पर काम शुरू कर देंगे। यह अग्नि सीरीज की सबसे आधुनिक 'इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल' होगी। माना जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। यह मिसाइल एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी, जिससे यह एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकेगी।

रेल मंत्रालय ने 895 करोड़ रु. की परियोजनाओं को दी मंजूरी...कोलकाता मेट्रो,आद्रा ब्रिज होगा मजबूत

नई दिल्ली,02 मई 2026। रेल मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में रेलवे अवसंरचना को मजबूत करने और कोलकाता मेट्रो सेवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए 895.30 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में कोलकाता मेट्रो के पावर सिस्टम का उन्नयन और दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में एक अहम पुल का पुनर्निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से जहां एक ओर मेट्रो सेवाओं में सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर माल परिवहन और औद्योगिक कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोलकाता मेट्रो के नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए 671.72 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 7 नए ट्रैक्शन सबस्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिन पर 291.06 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, एस्प्लेनेड से कवि सुभाष (न्यू गरिया) तक पावर सिस्टम को 11 केवी से बढ़ाकर 33 केवी किया जाएगा, जिस पर 380.66 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस अपग्रेड के बाद मेट्रो सेवाओं की फ्रीक्वेंसी 5 मिनट से घटाकर 2.5 मिनट की जा सकेगी, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और तेज सेवा मिलेगी। वर्तमान सिस्टम 1980 के दशक का है और अपनी क्षमता सीमा तक पहुंच चुका है, ऐसे में यह उन्नयन अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे के तहत एमडीकेडी-डीएमए (मधुकुंडा-दामोदर) सेक्शन के बीच ब्रिज नंबर 520 (अप और डाउन लाइन)के पुनर्निर्माण के लिए 223.58 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। दामोदर नदी पर स्थित यह पुल 1903 और 1965 में निर्मित हुआ था और अब इसमें संरचनात्मक कमजोरी के संकेत मिले हैं। यह रेलखंड आसनसोल और टाटानगर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है और कोयला परिवहन के लिए अहम कॉरिडोर का हिस्सा है।

संपादकीय

ओपेक के हाथ से फिसलता तेल का बाजार

ओपेक यानी तेल निर्यातक देशों के संगठन का उदय तेल उत्पादक देशों की उस आकांक्षा से हुआ था,जिसके केंद्र में अपने संसाधनों, उत्पादन और आय पर अधिक नियंत्रण हासिल करने की इच्छा थी। 1960 में जब ईरान,इराक,कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने बगदाद में इस संगठन की स्थापना की,तो उनका उद्देश्य केवल तेल की कीमतों को प्रभावित करना नहीं था। इसके साथ वे उस वैश्विक व्यवस्था को भी बदलना चाहते थे, जिसमें तेल उत्पादक देशों के पास संसाधन तो थे,लेकिन कीमत, उत्पादन और आय पर निर्णायक प्रभाव विदेशी कंपनियों और उपभोक्ता देशों का था।

इस पृष्ठभूमि में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने को केवल उत्पादन कोटे पर मतभेद या क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के रूप में देखना अधूरा होगा। यह ऊर्जा संप्रभुता की बदलती परिभाषा का संकेत है। 1960 में तेल उत्पादक देशों के लिए सामूहिक मंच बनाना जरूरी था,लेकिन आज 2026 में यूएई जैसे देशों को अपना हित स्वतंत्र निर्णय लेने में है। ओपेक ने तेल उत्पादक देशों को सामूहिक शक्ति दी थी। यूएई अब वही नियंत्रण सामूहिक उत्पादन सीमाओं के बजाय अपनी क्षमता,अवसंरचना और दीर्घकालिक राष्ट्रीय रणनीति के आधार पर हासिल करना चाहता है।

ओपेक की ऐतिहासिक भूमिका निर्विवाद है। उसने तेल उत्पादक देशों को अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों और बड़े उपभोक्ता देशों के सामने सामूहिक शक्ति दी। 1970 के दशक में तेल केवल व्यापारिक वस्तु नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीति का केंद्रीय तत्व बन गया। सऊदी अरब ने अपने विशाल भंडार और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के कारण इस व्यवस्था में विशेष स्थान बनाया,लेकिन आज तेल बाजार पहले जैसा नहीं है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है। रूस,कनाडा,ब्राजील,गुयाना और अन्य गैर-ओपेक तेल उत्पादक देश वैश्विक आपूर्ति को प्रभावित कर रहे हैं। 2016 में ओपेक प्लस का विस्तार इसी बदली हुई वास्तविकता की स्वीकृति था।

ओपेक अप्रासंगिक तो नहीं हुआ,लेकिन तेल बाजार अब उसकी मूल संरचना से आगे निकल चुका है। यूएई की रणनीति भी इसी से जुड़ी है। वह केवल तेल निर्यातक देश बनकर नहीं रहना चाहता,बल्कि वह ऊर्जा,लाजिस्टिक्स,वित्त, तकनीक और वैश्विक व्यापार में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। तेल उत्पादन सीमा से बंधे रहना उसकी व्यापक राष्ट्रीय रणनीति से मेल नहीं खाता। उसके लिए यह केवल तेल उत्पादन का विषय नहीं,बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है। दुनिया में तेल की मांग अभी समाप्त नहीं हुई है,पर वैश्विक अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे विद्युतीकरण,स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु नीतियों की ओर बढ़ रही है।

ऐसे में कम लागत पर तेल निकालने वाले देशों के सामने बड़ा प्रश्न है कि क्या वे कीमतों को ऊंचा बनाए रखने के लिए उत्पादन सीमित रखें या अपने संसाधनों को समय रहते आय में बदलकर भविष्य की तैयारी करें? यूएई का झुकाव दूसरे विकल्प की ओर दिखाई देता है। ईरान-अमेरिका तनाव और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास की अस्थिरता ने इस सोच को और प्रासंगिक बना दिया है। पाइपलाइन अवसंरचना के कारण यूएई के पास सीमित ही सही, लेकिन ऐसा विकल्प है, जो संकट के समय खरीदारों को अतिरिक्त भरोसा देता है। इसका महत्व एशिया के लिए विशेष है। भारत,चीन,जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अब केवल तेल उपभोक्ता नहीं,बल्कि उसकी दिशा प्रभावित करने वाले बड़े आयातक हैं। उनकी मांग,रिफाइनिंग क्षमता और दीर्घकालिक अनुबंध तेल उत्पादक देशों की रणनीति को प्रभावित करते हैं। यदि यूएई अधिक लचीला और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बनता है,तो एशियाई देशों की आपूर्ति सुरक्षा मजबूत हो सकती है और ऊर्जा कीमतों से जुड़ा आर्थिक दबाव कुछ कम हो सकता है।

अमेरिका ऐसी व्यवस्था को सकारात्मक मान सकता है, जिसमें तेल बाजार पर कुछ सीमित उत्पादकों का प्रभाव कम हो। रूस के लिए यह बदलाव मिश्रित है। जहां एक तरफ ओपेक प्लस ने उसे औपचारिक सदस्यता के बिना तेल समन्वय में भूमिका दी,वहीं दूसरी तरफ ओपेक के कम प्रभावी होने से उसका लाभ होना भी सुनिश्चित है। सऊदी अरब के लिए यूएई का निर्णय चुनौती है, लेकिन इसे क्षेत्रीय टकराव का नाम देना सही नहीं होगा। सऊदी अरब अपने तेल भंडार और उत्पादन क्षमता के कारण हमेशा महत्वपूर्ण बना रहेगा। यूएई का कदम इस तरफ इशारा करता है कि खाड़ी की ऊर्जा राजनीति अब अधिक विविध हो रही है। अब खाड़ी देश अपनी-अपनी ऊर्जा प्राथमिकताओं के अनुसार अलग रास्ते अपना सकते हैं।

चूंकि कई देश अब भी ओपेक को उपयोगी मानते हैं,इसलिए बड़े पैमाने पर सदस्य देशों के बाहर निकलने की संभावना कम है। फिर भी यूएई का कदम दिखाता है कि ओपेक पहले की तरह सभी सदस्यों को एक समान उत्पादन नीति में बांधकर नहीं रख पाएगा। ईरान के संदर्भ में भी संतुलन जरूरी है। उसके पास बड़े ऊर्जा संसाधन हैं, पर प्रतिबंधों और निवेश की कमी ने उसकी क्षमता सीमित कर दी है। ओपेक कमजोर होगा तो ईरान और खाड़ी देशों के बीच संवाद का एक मंच कमजोर पड़ सकता है। यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में क्या कोई बदलाव ओआइसी और अरब लीग जैसे संगठनों में भी होंगे?

केवल अधिकार नहीं,जिम्मेदारी भी है पत्रकारिता की स्वतंत्रता

योगेश कुमार गोयल
नजफ्फगढ़,नई दिल्ली

भारत में प्रेस को सदैव लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी जाती रही है क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती में इसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कारण है कि स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बहुत अहम माना गया है लेकिन विड़म्बना है कि विगत कुछ वर्षों से यहां भी प्रेस स्वतंत्रता के मामले में लगातार कमी देखी जा रही है। इसीलिए प्रतिवर्ष 3 मई को 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' मनाया जाता है। कलम को तलवार से भी ज्यादा ताकतवर और तलवार की धार से भी ज्यादा प्रभावी इसीलिए माना गया है क्योंकि इसी की सजगता के कारण न केवल भारत में बल्कि अनेक देशों में पिछले कुछ दशकों के भीतर बड़े-बड़े घोटालों का पर्दाफाश हो सका, जिसके चलते बड़े-बड़े उद्योगपतियों, नेताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को एक ही झटके में अर्श से फर्श पर आना पड़ा। यही कारण हैं कि समय-समय पर कलम रूपी इस हथियार को भोथरा बनाने या तोड़ने के कुचक्र होते रहे हैं और विभिन्न अवसरों पर न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में सच की कीमत कुछ पत्रकारों को अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ती है। पिछले दशकों में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में स्थितियां काफी बदल गई हैं। आज दुनियाभर में पत्रकारों पर राजनीतिक,अपराधिक और आतंकी समूहों का सर्वाधिक खतरा है और भारत भी इस मामले में अछूता नहीं है। विड़म्बना है कि दुनियाभर के न्यूज रूम्स में सरकारी तथा निजी समूहों के कारण भय और तनाव में वृद्धि हुई है। पेरिस स्थित 'रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स' (आरएसएफ)अथवा 'रिपोर्टर्स विद आउट बॉर्डर्स' नामक संस्था द्वारा हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते रहे हैं,वे सदैव चौंकाने वाले होते हैं। हालांकि यह अलग बात है कि कुछ देश इस रिपोर्ट में जारी किए जाने वाले आंकड़ों को पूर्वाग्रह से प्रेरित बताकर खारिज भी करते रहे हैं।'रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स' एक ऐसा गैर-लाभकारी संगठन है,जो विश्वभर के पत्रकारों पर हमलों का दस्तावेजीकरण करने और मुकाबला करने के लिए कार्यरत है और प्रतिवर्ष'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स'अर्थात्'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' नामक रिपोर्ट पेश करता है। 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019' में उसने भारत सहित विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया था कि

किस प्रकार विश्वभर में पत्रकारों के खिलाफ घृणा हिंसा में बदल गई है, जिससे दुनियाभर में पत्रकारों में डर बढ़ा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 के अनुसार, 180 देशों की सूची में भारत 157 वें स्थान पर खिसक गया है जबकि 2025 में भारत 151 वें स्थान पर था यानी एक वर्ष में छह स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। इससे पूर्व 2024 में भारत 159 वें, 2023 में 161वें और 2022 में 150वें पायदान पर खड़ा था। यह रिपोर्ट प्रेस स्वतंत्रता के लिए भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट का संकेत देती है। रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों के साथ व्यवहार के लिए 'संतोषजनक' माने जाने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है लेकिन ऐसी संख्या भी कम नहीं है, जहां स्थिति 'बहुत गंभीर' है।

रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स द्वारा जारी दुनियाभर के देशों की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में भारत जहां 2024 में 2023 के मुकाबले दो पायदान ऊपर चढ़ा,वहीं 2023 में 2022 के मुकाबले 11 पायदान नीचे गिरा था और 2022 में भी 2021 की रैंकिंग के मुकाबले 8 स्थान नीचे फिसला था। 2021 की रैंकिंग में भारत का स्थान 142 वां था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 की सूची में नॉर्वे शीर्ष पर है। भारत के लोकतंत्र को तो दुनिया का सबसे सफल और बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है,वहीं अगर नार्वे जैसा छोटा सा देश प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में लगातार शीर्ष स्थान पर विराजमान है और चीन को छोड़कर भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश भी बेहतर स्थिति में है तो यह स्थिति भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए सही स्थिति नहीं है। ऐसे में हमें गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है कि हम इस मामले में वर्ष दर वर्ष क्यों फिसल रहे हैं? प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में यह गिरावट स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

प्रेस की स्वतंत्रता में कमी आने का सीधा और स्पष्ट संकेत यही है कि लोकतंत्र की मूल भावना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार निहित है, उसमें धीरे-धीरे कमी आ रही है। समाज में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए इसे लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ माना गया है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार खासकर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा बगैर किसी जानकारी को जांचे-परखे केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए झूठ का बवंडर तैयार किया जाता है,उसे देखकर कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है मानो टीवी चैनल पर समाचार या कोई न्यूज कार्यक्रम नहीं बल्कि कोई मसालेदार राजनीतिक फिल्म चल रही हो। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही हो रहा है कि लोगों का विश्वास मीडिया पर निरंतर कम हो रहा है और लोगों का आकर्षण सोशल मीडिया की ओर बढ़ रहा है, जहां पहले से ही फेक न्यूज बहुत बड़ी समस्या मौजूद है तथा एआई इस समस्या को और ज्यादा बढ़ाने में बड़ा योगदान दे रही है। भारतीय संविधान में प्रेस को अलग से स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है बल्कि उसकी स्वतंत्रता भी नागरिकों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता में ही निहित है और देश की एकता तथा अखण्डता खतरे में पड़ने की स्थिति में इस स्वतंत्रता को बाधित भी किया जा सकता है किन्तु ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं होने पर भी देश में पत्रकारिता का चुनौतीपूर्ण बनते जाना लोकतंत्र के हित में कदापि नहीं है बल्कि यह स्पष्ट रूप से कुछ शक्तियों द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के चौथे स्तंभ को ध्वस्त करने का ही प्रयास माना जाता है। कल्पना की जा सकती है कि प्रेस की स्वतंत्रता अगर इसी प्रकार सवालों के घेरे में रही तो पत्रकार कैसे पारदर्शिता के साथ अपने कार्य को अंजाम देते रहेंगे? प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के प्रयासों के चलते कैसे सच को उजागर कर उसे निष्पक्ष तरीके से जनता तक पहुंचाया जाना संभव होगा? देश में प्रेस की स्वतंत्रता बरकरार रहे,इसके लिए किसी मीडिया संस्थान से जुड़े पत्रकार हों या स्वतंत्र पत्रकार,उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाए जाने की सख्त दरकार है ताकि बगैर किसी दबाव या भय के पत्रकार अपना कर्त्तव्य बखूबी निभाते रहें। हालांकि यह भी बेहद जरूरी है कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ 'प्रेस' को भी अपनी सीमाओं और मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए अपनी स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करना चाहिए।

अगले साल मार्च में पता चलेगा यूपी में 'हम कितने हैं'

अजय कुमार
लखनऊ,उत्तरप्रदेश

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 2011 की जनगणना के बाद कितनी वृद्धि हुई है,इसका सटीक आंकड़ा जानने के लिए 16वीं जनगणना 22 मई 2026 से शुरू हो रही है। यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में मकानों की संख्या, उनकी स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं का डेटा एकत्र किया जाएगा,जबकि दूसरे चरण में वास्तविक जनसंख्या की गणना होगी। लाखों कर्मियों को इस कार्य के लिए तैनात किया गया है और पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से संचालित होगी। अंतिम आंकड़े 1 मार्च 2027 को घोषित हो जाएंगे। यह जनगणना न केवल आबादी का सही आंकड़ा देगी,बल्कि राज्य की विकास योजनाओं,संसाधनों के वितरण और नीतियों को आकार देने में भी मदद करेगी। ऐसा लग रहा है कि जनगणना के आंकड़े आने के आसपास ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आएंगे,क्योंकि मोदी का कार्यकाल अगले साल मार्च में पूरा हो रहा है। खैर,उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है,जहां 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 19.98 करोड़ लोग रहते थे। उसके बाद 15 वर्षों में आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है। अनुमानों के अनुसार,वर्तमान आबादी 24 करोड़ से अधिक हो चुकी है, लेकिन सटीक संख्या जानने के लिए ही यह नई जनगणना आवश्यक है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसकी तैयारियां लंबे समय से की हैं। महामारी और अन्य चुनौतियों के बावजूद प्रक्रिया को समय पर शुरू करने का निर्णय सराहनीय है। पहले चरण में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के घरों का सर्वे होगा, जिसमें बिजली,पानी,शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। इससे राज्य के विकास के स्तर का पता चलेगा और कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।

दूसरे चरण में जनसंख्या गणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति का नाम, उम्र, लिंग, शिक्षा, रोजगार और प्रवास जैसे विवरण दर्ज किए जाएंगे। डिजिटल माध्यम से यह कार्य तेज और त्रुटिरहित होगा। कर्मियों को हैंडहेल्ड डिवाइस दिए जाएंगे, जिनमें जीपीएस की मदद से स्थान का पता चलेगा। इससे डुप्लिकेट एंट्री या गलतियां कम होंगी। लाखों कर्मचारियों की तैनाती से ग्रामीण इलाकों तक पहुंच सुनिश्चित होगी। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में यह चुनौतीपूर्ण है,जहां पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्रों में अलग-अलग जनघनत्व है। जनगणना के आंकड़े संसद सीटों के पुनर्वितरण,विधानसभा क्षेत्रों के सीमांकन और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान में उपयोगी साबित होंगे।इस जनगणना का महत्व कई स्तरों पर समझा जा सकता है। सबसे पहले, 2011 के बाद जन्म दर,मृत्यु दर और प्रवास पैटर्न में बदलाव आया है। युवा आबादी बढ़ी है,लेकिन बेरोजगारी और शिक्षा के स्तर पर सवाल उठे हैं। जनगणना से पता चलेगा कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं,महिलाओं की भागीदारी कितनी है और बुजुर्गों की संख्या क्या है। दूसरा, कोविड महामारी ने स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी उजागर की,अब आंकड़ों से अस्पतालों और डॉक्टरों की आवश्यकता का आकलन होगा। तीसरा, जलवायु परिवर्तन और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आबादी का घनत्व जानना जरूरी है। उदाहरण के लिए,गंगा-यमुना के मैदानी इलाकों में आबादी अधिक है,जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कम। इन आंकड़ों से सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और आवास योजनाएं बेहतर होंगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी।

आनंद और अवसाद और सुख और पीड़ा,जीवन के अलग-अलग सोपान

संजीव ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

सुख और दुःख दो ऐसे सोपान हैं जिन पर चलकर ही मनुष्य अपनी संपूर्णता को समझ पाता है।

जीवन कभी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता,उसमें उतार-चढ़ाव,सुख-दुःख,आशा-निराशा, संभाव नाएं और आशंकाएं निरंतर एक-दूसरे में गुंथी रहती हैं। जैसे प्रकृति में दिन और रात का क्रम है, जैसे ऋतुएं बदलती हैं,वैसे ही मनुष्य के भीतर भी भावनाओं का आवागमन होता रहता है। यदि केवल आनंद ही होता तो उसकी पहचान भी संभव नहीं होती और यदि केवल अवसाद ही होता तो जीवन का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता,इसलिए इन दोनों का सह-अस्तित्व ही जीवन को अर्थ देता है।

गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा कि जीवन दुःखों से भरा है, परंतु उससे मुक्ति का मार्ग भी संभव है। यह दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि अवसाद स्थायी सत्य नहीं बल्कि एक परिवर्तनशील अवस्था है जिसे समझकर पार किया जा सकता है, इसी तरह स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध आह्वान उठो,जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए जीवन के संघर्षों के बीच आशा की ज्योति बनकर मार्ग दिखाता है,जब मनुष्य अवसाद में डूबता है तब उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है,परंतु यही वह क्षण होता है जब भीतर छिपी शक्ति जागृत हो सकती है,इतिहास इस बात का साक्षी है कि महान व्यक्तित्वों ने गहरे अवसाद और संघर्षों को पार करके ही ऊंचाइयों को छुआ है, अब्राहम लिंकन का जीवन इसका सशक्त उदाहरण है,उन्होंने अनेक बार असफलताओं का सामना किया, चुनावों में हार का सामना किया, व्यक्तिगत जीवन में गहन पीड़ा झेली, फिर भी उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा और अंततः वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने,यह हमें सिखाता है कि अवसाद अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार भी हो सकता है। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने कहा था कि मनुष्य अपने विचारों से निर्मित प्राणी है,वह जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यह कथन स्पष्ट करता है कि आनंद और अवसाद दोनों का मूल हमारे भीतर है, परिस्थितियां बाहरी होती हैं परंतु उनका प्रभाव हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, यदि हम सकारात्मक दृष्टि बनाए रखें तो कठिन परिस्थितियों में भी आशा की किरण दिखाई देती है। जीवन में सुख के क्षण हमें ऊर्जा और उत्साह देते हैं जबकि दुःख के क्षण हमें धैर्य,सहनशीलता और गहराई प्रदान करते हैं,यदि केवल आनंद ही हो तो मनुष्य सतही बन सकता है और यदि केवल अवसाद ही हो तो वह टूट सकता है,परंतु इन दोनों के संतुलन से ही वह परिपक्व और संवेदनशील बनता है। आधुनिक समय में अवसाद एक गंभीर सामाजिक और मानसिक समस्या के रूप में उभर रहा है, तेज प्रतिस्पर्धा, अकेलापन, सामाजिक अपेक्षाएं और असफलता का भय मनुष्य को भीतर से कमजोर कर रहा है, ऐसे समय में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि अवसाद कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक संकेत है कि हमें अपने भीतर झांकने और स्वयं को समझने की आवश्यकता है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की पंक्ति यदि तुम रोओगे क्योंकि सूर्य अस्त हो गया है,तो तुम तारों को नहीं देख पाओगे । जीवन के गहन सत्य को उद्घाटित करती है कि हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है, आनंद और अवसाद दोनों ही हमारे शिक्षक हैं,आनंद हमें कृतज्ञता और संतोष सिखाता है जबकि अवसाद हमें आत्ममंथन और आत्मबोध की ओर ले जाता है,जब मनुष्य अपने दुःख को समझता है तो वह दूसरों के दुःख को भी अनुभव करने लगता है और यहीं से करुणा, संवेदनशीलता और मानवता का विकास होता है, इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अवसाद भी जीवन का एक आवश्यक अध्याय है, यह हमें भीतर से मजबूत बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जीवन की यात्रा में अनेक मोड़ आते हैं, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी संबंधों में मधुरता होती है तो कभी कटुता,कभी आशाएं पंख फैलाती हैं तो कभी आशंकाएं मन को घेर लेती हैं, परंतु इन सबके बीच यदि हम संतुलन बनाए रखें, धैर्य और विश्वास को थामे रखें और यह समझें कि हर स्थिति अस्थायी है तो हम जीवन को अधिक सहजता और संतुलन के साथ जी सकते हैं। डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते है। यह कथन आशा और संभावनाओं की शक्ति को दर्शाता है,जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं,यदि हमारे भीतर एक लक्ष्य और एक विश्वास जीवित है तो हम हर अवसाद को पार कर सकते हैं।

आईसीयू के अमानवीय एवं अनैतिक पक्षों की निगरानी जरूरी

ललित गर्ग
पटपड़गंज,दिल्ली-92

देश में स्वास्थ्य सेवा की वर्तमान स्थिति पर विचार करते समय एक अत्यंत चिंताजनक,मानवीय और संवेदनशील प्रश्न सामने आता है-क्या चिकित्सा अब सेवा न रहकर व्यवसाय का कठोर रूप एवं एक त्रासदी बनती जा रही है? विशेष रूप से निजी अस्पतालों के आईसीयू (गहन चिकित्सा कक्ष) से जुड़े मामलों ने इस प्रश्न को और अधिक तीखा बना दिया है। ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए हैं,जहां मरीज के चिकित्सकीय रूप से स्थिर हो जाने के बावजूद उसे आईसीयू में रोके रखा जाता है। इसके पीछे का कारण अक्सर चिकित्सा की अनिवार्यता नहीं,बल्कि आर्थिक लाभ की निरंतर चलती प्रक्रिया होती है। यह स्थिति न केवल चिकित्सा के नैतिकता एवं सेवाभावना पर प्रश्नचिह्न लगाती है,बल्कि मानवता की मूल संवेदनाओं को भी झकझोरती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईसीयू के लिए एकसमान दिशानिर्देशों की आवश्यकता पर बल देना इस गंभीर समस्या की स्वीकारोक्ति भी है और समाधान की दिशा में एक सार्थक पहल भी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जो मरीज चिकित्सकीय रूप से स्थिर हो चुके हैं या जिन्हें गहन निगरानी अथवा जीवन रक्षक उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अनावश्यक रूप से आईसीयू में नहीं रखा जाना चाहिए। यह निर्देश केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि गहरे नैतिक आधार पर टिका हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि चिकित्सा का मूल उद्देश्य जीवन की रक्षा और पीड़ा का निवारण है, न कि आर्थिक लाभ का अधिकतमकरण।

सही मायनों में सुप्रीम कोर्ट के ये दिशानिर्देश एक सरल व सामान्य सिद्धांत की पुष्टि करते हुए इस विसंगति को दूर करने का प्रयास करते हैं कि किसी भी अस्पताल का आईसीयू मरीज की अनिश्चितकालीन देखभाल के लिए नहीं होता है। इन दिशानिर्देशों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि चिकित्सकीय रूप से स्थिर हो चुके या जिन मरीजों के अंगों को बाहरी सहायता अथवा शारीरिक निगरानी की आवश्यकता नहीं होती,उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जानी चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शीर्ष अदालत ने समस्या के यथाशीघ्र समाधान की जरूरत पर बल दिया है। अदालत ने डॉक्टरों की प्रतिष्ठा को संरक्षित करते हुए चिकित्सा संस्थानों व अस्पतालों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया है। निश्चित तौर पर आधुनिक चिकित्सा खर्चीली हो गई और बेहतर सुविधाओं के लिए बड़ी रकम चुकानी होती है। लेकिन इस व्यवस्था में सेवा का भाव न होकर व्यवसाय की भावना का अधिक होना चिन्ताजनक है। इसी के कारण इसमें अनेक विसंगतियां एवं क्रूरताएं व्याप्त होती जा रही है,इसके नियमन का कार्य यूं तो देश के नीति-नियंताओं और शासन-प्रशासन को करना चाहिए था। लेकिन विडंबना यह है कि अदालत को ऐसे मामलों में पहल करनी पड़ती है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक समान गहन चिकित्सा ईकाई दिशानिर्देशों की जरूरत बताना विसंगतियों से जूझती आईसीयू प्रणाली के लिए एक आशा की किरण लेकर आई है। वास्तव में आईसीयू एक विशेष सुविधा है, जिसका उपयोग केवल उन मरीजों के लिए होना चाहिए जिनकी स्थिति गंभीर हो और जिन्हें निरंतर निगरानी या अत्याधुनिक उपकरणों की आवश्यकता हो। किंतु जब इस सुविधा का उपयोग लाभ कमाने के साधन के रूप में होने लगे, तब यह व्यवस्था एक प्रकार की अमानवीयता में परिवर्तित हो जाती है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए आईसीयू का खर्च अक्सर असहनीय होता है। एक दिन का खर्च हजारों से लेकर

लाखों तक पहुंच सकता है। ऐसे में यदि मरीज को अनावश्यक रूप से वहां रोका जाता है,तो यह केवल आर्थिक शोषण नहीं,बल्कि मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न भी है। यह स्थिति इसलिए भी जटिल हो जाती है क्योंकि आमजन को चिकित्सा प्रक्रियाओं की गहन जानकारी नहीं होती। मरीज के परिजन डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के निर्देशों पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। इस निर्भरता का दुरुपयोग तब होता है जब पारदर्शिता का अभाव होता है। कई बार मरीज को वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया जाता और उसे आईसीयू में बनाए रखने के निर्णय को अंतिम सत्य की तरह प्रस्तुत कर दिया जाता है। इस प्रकार एक अस्पष्टता का वातावरण बनता है, जिसमें सत्य और लाभ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है।

यदि हम इस समस्या की जड़ में जाएं, तो पाएंगे कि यह केवल अस्पतालों या डॉक्टरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक व्यवस्थागत विफलता का परिणाम है। आजादी के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सरकार के अधीन रखकर यह अपेक्षा की गई थी कि ये क्षेत्र जनसेवा के आदर्श उदाहरण बनेंगे। किंतु समय के साथ आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण के प्रभाव ने इन क्षेत्रों की दिशा बदल दी। शिक्षा जहां एक महंगा व्यवसाय बन गई, वहीं चिकित्सा सेवा भी धीरे-धीरे लाभ कमाने का माध्यम बनती चली गई। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आज चिकित्सा क्षेत्र में एक प्रकार की व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसमें मरीज एक ग्राहक की तरह देखा जाने लगा है। बड़े-बड़े निजी अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर तेजी से बढ़ रहे हैं, जो एक दृष्टि से सकारात्मक है,लेकिन जब इन सुविधाओं का उपयोग केवल आर्थिक लाभ के लिए होने लगे, तब यह चिंता का विषय बन जाता है। अस्पतालों की संख्या बढ़ना अच्छा है, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली में लोभ की प्रवृत्ति का बढ़ना जहां गहन घातक है, वही उसमें मानवीय संवेदना और नैतिकता का समावेश होना अधिक आवश्यक है।

इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश एक आशा की किरण के रूप में सामने आते हैं। इन दिशानिर्देशों में न केवल मरीजों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई है, बल्कि अस्पतालों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। नर्स और मरीज के अनुपात, विशेषज्ञों की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रयास स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और न्यायसंगत बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकता है। किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि किसी भी नीति या दिशानिर्देश की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। भारत में अनेक बार देखा गया है कि अच्छे इरादों से बनाई गई योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह जाती हैं। यदि इन दिशानिर्देशों का पालन भी आधे-अधूरे मन से किया गया, तो यह प्रयास भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

रिंग बांध तालाब अतिक्रमण हटाने में हंगामा....

निगम टीम से अभद्रता,भू-माफिया फरार,FIR दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 मई 2026 (घटती-घटना)।

शहर के रिंग बांध तालाब में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को शनिवार को विरोध,अभद्रता और धमकियों का सामना करना पड़ा। कार्रवाई के दौरान कुछ कब्जाधारियों ने निगम कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज करते हुए कहा...'अधिकारी को बुलाओ,डंडा लेकर आओ।' इस घटनाक्रम से मौके पर अफरा-तफरी और तनाव की स्थिति बन गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार,रिंग बांध तालाब की शासकीय भूमि पर लंबे समय से मिट्टी डालकर अवैध कब्जा किया जा रहा था। प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम की उड़नदस्ता टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। जैसे ही टीम ने तालाब क्षेत्र से मिट्टी हटाने की कार्रवाई शुरू की,कुछ लोग मौके पर पहुंचकर विरोध करने लगे और कार्य में बाधा डालने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार,कब्जाधारियों ने न केवल निगम कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया,बल्कि कार्रवाई रुकवाने के लिए दबाव भी बनाया। उन्होंने जमीन पर स्टे होने का दावा किया और ट्रैक्टर में भरी मिट्टी तक गिरवा दी, जिससे कुछ समय के लिए कर्मचारी पीछे हट गए। इस बीच,घटना की जानकारी मिलते ही नगर निगम,राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। प्रशासन की सख्ती देखते ही विरोध कर रहे लोग मौके से भाग निकले। अधिकारियों की मौजूदगी में दोबारा कार्रवाई शुरू की गई और तालाब से मिट्टी हटाने का काम जारी रखा गया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भूमि पर किसी प्रकार का वैधानिक स्टे नहीं है और कब्जा पूरी तरह अवैध है।

वीडियो से होगी पहचान : घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज

देर शाम बस स्टैंड के पास स्थित जमीन विवाद को लेकर संबंधित आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें शासकीय कार्य में बाधा, गाली-गलौज और अन्य धाराएं जोड़ी गई हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

वरिष्ठ पत्रकार का दावा

वरिष्ठ पत्रकार आलोक शुक्ला ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रोकने के लिए कुछ असामाजिक तत्व मौके पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग निकले।

प्रशासन की सख्ती बरकरार

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर के तालाबों और जल स्रोतों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा और बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शराब बनाने से मना करने पर पत्नी ने पति पर डाला गर्म माड़,गंभीर रूप से झुलसा

दरिमा थाना क्षेत्र की घटना,आरोपी पत्नी फरार,पुलिस कर रही तलाश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 मई 2026 (घटती-घटना)।

दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम नवाबांध में घरेलू विवाद के दौरान पत्नी द्वारा पति पर गर्म माड़ उढ़ेलने का मामला सामने आया है। घटना में पति गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार ग्राम नवाबांध निवासी केन्नीलाल राजवाड़े की पत्नी रामबाई अपने छोटे बेटे के साथ घर में महुआ शराब बनाकर बेचती थी। केन्नीलाल को यह काम पसंद नहीं था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। 29 अप्रैल की रात करीब 9 बजे केन्नीलाल घर के आंगन में खाना खाने के बाद आराम कर रहा था। इसी दौरान उसने पत्नी को शराब बनाकर बेचने से मना किया।

इस बात पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। गुस्से में आकर रामबाई ने गर्म माड़ पति के ऊपर उढ़ेल दिया, जिससे उसका सीना,गर्दन और पीठ बुरी तरह झुलस गए और शरीर पर फफोले पड़ गए। घटना के बाद केन्नीलाल के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका बड़ा बेटा राजेंद्र मौके पर पहुंचा और उसे तत्काल दरिमा अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है।

अपराध दर्ज,पत्नी फरार : पीड़ित की शिकायत पर दरिमा पुलिस ने आरोपी पत्नी रामबाई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3) और 118(1) के तहत अपराध दर्ज किया है। घटना के बाद से आरोपी पत्नी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है।

अम्बिकापुर शहरी क्षेत्र में जनगणना कार्य का शुभारंभ,नागरिकों से सहयोग की अपील

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 मई 2026 (घटती-घटना)।

नगर पालिक निगम,अम्बिकापुर क्षेत्रांतर्गत आज से राष्ट्रीय जनगणना कार्य का शुभारंभ किया गया। इस महत्वपूर्ण अभियान के अंतर्गत नियुक्त प्रगणक एवं पर्यवेक्षक द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में घर-घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्रित की जाएगी। नगर निगम आयुक्त श्री डी एन कश्यप द्वारा जारी निर्देशानुसार जनगणना कार्य को चरणबद्ध तरीके से संपादित किया जाएगा। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान प्रगणक नागरिकों से उनके परिवार, शिक्षा, व्यवसाय तथा उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। आयुक्त,नगर पालिक निगम अम्बिकापुर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि जनगणना एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व है, जो शहर के समग्र विकास एवं भविष्य की योजनाओं के निर्माण का आधार बनता है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि जब भी प्रगणक उनके घर पहुंचें,उन्हें सही एवं सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं। सभी प्रगणकों को अधिकृत पहचान पत्र जारी किए गए हैं, अतः नागरिक जानकारी देने से पूर्व उनकी पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं। नगर निगम प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि नागरिकों से प्राप्त समस्त जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल शासकीय प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

सही दवा शुद्ध आहार'अभियान अंतर्गत वैक्सीन सेंटर एवं फार्मेसी की सघन जांच

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 मई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन,खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा कलेक्टर, सरगुजा के निर्देशानुसार जिले में 27 अप्रैल से 11 मई 2026 तक 'सही दवा शुद्ध आहार,यही छत्तीसगढ़ का आधार' थीम पर 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य एवं औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में 01 मई 2026 को जिले के 07 निजी अस्पतालों एवं क्लीनिकों में संचालित वैक्सीन स्टोर एवं फार्मेसी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किए गए संस्थानों में मासूम फार्मेसी, संकल्प हॉस्पिटल फार्मेसी,यशोदा फार्मेसी,राजरानी हॉस्पिटल (एमआरएम फार्मेसी),किलकारी हॉस्पिटल फार्मेसी,शिशु मंगलम हॉस्पिटल (सिटी फार्मेसी) तथा हॉलीक्रास हॉस्पिटल फार्मेसी शामिल हैं। जांच के दौरान वैक्सीन एवं अन्य औषधियों के सुरक्षित भंडारण, निर्धारित तापमान के पालन एवं कोल्ड चेन व्यवस्था का गहन परीक्षण किया गया। साथ ही अभिलेख संधारण,दवाओं की क्रय-विक्रय प्रक्रिया तथा बिल/इनवॉइस की उपलब्धता का भी सत्यापन किया गया। निरीक्षण दल द्वारा संबंधित संचालकों को एक्सपायरी दवाओं को पृथक रखकर नियमानुसार नष्ट करने, औषधियों की ट्रेसबिलिटी बनाए रखने तथा केवल अधिकृत स्रोतों से ही दवाएं क्रय करने के निर्देश दिए गए।

सरगुजा में कांग्रेस की समीक्षा बैठक...संगठन को मजबूत करने पर जोर,निष्क्रिय पदाधिकारियों को चेतावनी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 मई 2026 (घटती-घटना)।

कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं छत्तीसगढ़ की सहप्रभारी सुश्री जरिता लैतफलांग की अध्यक्षता में शनिवार को सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी की समीक्षा बैठक राजीव भवन में आयोजित की गई। बैठक में नवगठित कार्यकारिणी के सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष,मोर्चा संगठन-विभाग और विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जरिता लैतफलांग ने कहा कि उदयपुर अधिवेशन के संकल्प के अनुरूप संगठन में अनुसूचित जाति,जनजाति,पिछड़ा वर्ग, महिलाओं,अल्पसंख्यकों और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता है। उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इसे अधिकार के बजाय'भीख' के रूप में

प्रस्तुत कर रही है। उनका कहना था कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं को अधिकार देना चाहती, तो मौजूदा सीटों पर ही आरक्षण लागू करती,न कि सीटों की संख्या बढ़ाकर। उन्होंने संगठन में आधुनिक तकनीक के उपयोग और कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया। साथ ही निष्क्रिय पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी चुनावों को देखते हुए सभी को सक्रिय भूमिका निभानी होगी, अन्यथा सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए स्थान छोड़ना पड़ेगा। बैठक में पूर्व केबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि एक ओर भाजपा महिलाओं के सम्मान की बात करती है,वहीं दूसरी ओर महिला उत्पीड़न के आरोपियों को संरक्षण देती है,जो उसका दोहरा चरित्र दर्शाता है। बैठक की शुरुआत में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि जिले सहित सभी ब्लॉक कमेटियों में कार्यकारिणी का गठन उदयपुर संकल्प के अनुसार पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि जिले के लगभग 95 प्रतिशत बूथ,पंचायत और वार्ड स्तर पर समितियों का गठन कर लिया गया है।

निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने संगठन की मजबूती की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि बूथ, पंचायत और वार्ड स्तर के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के इतिहास,वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और विचारधारा से अवगत कराने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। बैठक को कांग्रेस उपाध्यक्ष राजीव सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा सोनी ने भी संबोधित किया।

आदिवासी नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म मामला: कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरिता लैतफलांग पहुंचीं वंदना,पीड़ितों से मुलाकात

जांच दल ने भी की पूछताछ,प्रशासन पर लापरवाही और दबाव बनाने के आरोप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 मई 2026 (घटती-घटना)।

नाबालिग आदिवासी बच्चियों के साथ हुए सामूहिक अनाचार के मामले को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं छत्तीसगढ़ की सहप्रभारी जरिता लैतफलांग ने ग्राम वंदना पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित बच्चियों व उनके परिजनों से मुलाकात की। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस द्वारा गठित जांच दल भी मौजूद रहा, जिसने पूरे मामले की जानकारी ली और प्रशासनिक कार्यवाही में कथित गफलतों की पड़ताल की। करीब एक घंटे तक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और जांच दल की महिला सदस्यों ने पीड़ित बच्चियों व उनके परिवारों से एकांत में बातचीत की। इस दौरान बच्चियों द्वारा बताए गए घटनाक्रम को लेकर उन्होंने गहरी चिंता जताई। जरिता लैतफलांग ने कहा कि बच्चियों ने जो विवरण दिया है, वह बेहद भयावह और झकझोर देने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गंभीर मामले को पुलिस और प्रशासन द्वारा दबाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि यह सोचकर मामला दबाया जा रहा है कि पीड़ित बच्चियां आदिवासी समाज से हैं,तो यह पूरी तरह गलत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीड़ित परिवारों को अब भी धमकाया जा रहा है और मामले को दबाने की कोशिश जारी है।

जांच और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल : कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस पुलिस अधिकारी ने प्रारंभिक जांच में अपराध दर्ज नहीं किया,वही अब भी मामले की विवेचना कर रहा है,जो गंभीर सवाल खड़े करता है। साथ ही उस चिकित्सक पर भी कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाया,जिसने कथित रूप से गलत रिपोर्ट दी थी। उन्होंने मांग की कि संबंधित पुलिस अधिकारी और चिकित्सक के खिलाफ साक्ष्य मिटाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की जाए।

निष्पक्ष जांच की मांग : उन्होंने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है और दोषी अधिकारियों के हाथ में जांच रहना प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाता है। कांग्रेस द्वारा गठित जांच दल दो दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने अपना रवैया नहीं बदला तो कांग्रेस पीड़ितों के पक्ष में आगे आंदोलन और कानूनी कार्रवाई करेगी।

सरकार पर निशाना

जरिता लैतफलांग ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं, इसके बावजूद इस घटना पर उनका कोई बयान नहीं आना चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सम्मान और सुशासन की बात करने वाली सरकार में महिला अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं और आरोपियों को संरक्षण मिल रहा है।

ट्रक की चपेट में आने से मजदूर की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 मई 2026 (घटती-घटना)।

ट्रक को बैक करते समय सामान उतार रहा सहयोगी ट्रक के पहिए के नीचे आ गया,क्षेत्रीय अस्पताल से रिफर करने पर अंबिकापुर लाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, बलरामपुर जिला के कुसमी का राजकुमार पिता स्व. बलभोर रजवार एक मई को सुबह करीब 9 बजे ट्रक क्रमांक सीजी 14 एमएम 2098 से सामान उतारते समय गिर गया,और ट्रक का पहिया उसके ऊपर से गुजर गया। घायल अवस्था में उसे कुसमी स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया,यहां से रिफर करने पर स्वजन मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे,यहां आपातकालीन चिकित्सा परिसर में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में स्थानीय पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया है।

जेल से छुड़ाने का झांसा देकर 50 हजार की ठगी

दुष्कर्म मामले में बंद युवक की मां से आरोपियों ने लिया पैसा, केस दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 मई 2026 (घटती-घटना)।

दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद युवक को छुड़ाने का झांसा देकर 50 हजार रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। मणिपुर थाना पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सितंबर 2024 में एक युवक को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसके परिजन जमानत के प्रयास में लगे थे। इसी दौरान युवक की मां रामबाई,निवासी अखोरा खुर्द (जिला बलरामपुर), अपनी बहन के यहां मेण्ड्राकला गई थी। यहां उसकी मुलाकात संदीप लकड़ा और सुरेंद्र लकड़ा से हुई। दोनों ने भरोसा दिलाया कि वे उसके बेटे को जेल से छुड़ा देंगे,जिसके लिए 70 हजार रुपए लगेंगे। आरोपियों ने पहले 50 हजार रुपए देने और बाकी 20 हजार रुपए बाद में देने की बात कही। पीड़िता ने खेत गिरवी रखकर 50 हजार रुपए का इंतजाम किया और 28 सितंबर 2024 को अपने पति के साथ मेण्ड्राकला पहुंची। वहां आरोपियों ने मोटरसाइकिल से आकर फोनपे के जरिए 50 हजार रुपए ले लिए। इसके बाद भी जब युवक जेल से नहीं छूटा तो पीड़िता ने आरोपियों से संपर्क किया और पैसे वापस मांगे। आरोप है कि आरोपियों ने पैसे लौटाने से इनकार करते हुए धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर मणिपुर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सुशासन तिहार के तहत लुण्ड्रा एवं बतौली विकासखंड में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 मई 2026 (घटती-घटना)।

सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत सरगुजा जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज लुण्ड्रा विकासखंड के ग्राम पंचायत डकई एवं बतौली विकासखंड के ग्राम चिरंगा में जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया गया।

शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा तकरीबन 27 विभागीय स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा,खाद्य,स्वास्थ्य,शिक्षा,कृषि, आजीविका,पंचायत एवं ग्रामीण विकास की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं शिविर स्थल में ही आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी, समस्याओं का मौके पर निराकरण : लुण्ड्रा के डकई में आयोजित शिविर में मांग 385 और शिकायत 12 कुल 397 आवेदन प्राप्त हुए, वहीं मौके पर 46 मांग आवेदनों का निराकरण हुआ। वहीं बतौली के चिरंगा में आयोजित शिविर में मांग 341 एवं शिकायत 1 कुल 342 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें मौके पर मांग के 98 आवेदनों का निराकरण किया गया दोनों शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। ग्रामीणों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें से अनेक प्रकरणों का त्वरित निराकरण स्थल पर ही किया गया, जबकि शेष आवेदनों के शीघ्र निराकरण हेतु संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

शिक्षक बने अफसर,पढ़ाई हुई बेअसर...एमसीबी जिला शिक्षा में फिसड्डी

सबसे अनुभवी टीचर,फिर भी सबसे खराब परिणाम-आखिर गलती कहां?

पढ़ाई पीछे...पदभार आगे : एमसीबी बोर्ड रिजल्ट ने खोली पोल

- नेतागिरी या पढ़ाई? एमसीबी के स्कूलों में क्या है प्राथमिकता
- शिक्षक पढ़ाएं या ऑफिस चलाएं? एमसीबी का रिजल्ट बना बड़ा सवाल
- नया जिला,पुरानी समस्या एमसीबी शिक्षा में सबसे पीछे
- डबल रोल में फेल सिस्टम में शिक्षक भी अधिकारी,रिजल्ट सबसे कमजोर
- क्लासरूम खाली,फाइलें भारी और एमसीबी में शिक्षा व्यवस्था चरमराई
- तनख्वाह पूरी,पढ़ाई अधूरी? एमसीबी के परिणामों ने उठाए गंभीर सवाल
- जिम्मेदारी ज्यादा,परिणाम शून्यः एमसीबी शिक्षा मॉडल पर प्रश्नचिह्न
- कागजों में व्यवस्था,जमीन पर फेलः एमसीबी शिक्षा की असल तस्वीर

छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026. 10वीं बनाम 12वीं (तुलनात्मक चार्ट)

जिला	10वीं रैंक	10वीं %	12वीं रैंक	12वीं %	प्रदर्शन विश्लेषण
कोरिया	5	93.02	1	95.64	12वीं में जबरदस्त उछाल
बीजापुर	1	96.06	2	95.03	दोनों में लगातार टॉप
कांकेर	3	93.68	3	93.75	स्थिर उत्कृष्ट प्रदर्शन
जशपुर	4	93.29	4	93.32	संतुलित रिजल्ट
नारायणपुर	2	94.80	12	86.92	12वीं में गिरावट
रायपुर	27	71.05	15	84.79	12वीं में सुधार, पर कमजोर स्थिति
बिलासपुर	30	65.30	27	79.19	दोनों में कमजोर प्रदर्शन
दुर्ग	31	63.12	29	77.91	शिक्षा हब, लेकिन निचले स्तर पर
सरगुजा	16	83.09	24	80.56	गिरावट
सूरजपुर	17	82.75	13	86.46	सुधार दिखा
रायगढ़	18	80.06	19	83.45	मध्यम प्रदर्शन
महासमुंद	19	79.35	22	80.89	हल्की गिरावट
कोरबा	22	77.58	18	83.48	सुधार
धमतरी	23	76.18	17	84.18	अच्छा सुधार
बालोद	29	65.94	30	77.79	कमजोर
सक्ति	28	68.78	31	72.07	लगातार गिरावट
जांजगीर-चांपा	32	59.90	32	65.73	निचले स्तर पर स्थिर
MCB	33	59.12	33	62.40	सबसे कमजोर जिला

10वीं में 59.12% और 12वीं में 62.40%
सभी जिलों में सबसे कमजोर जिला: एमसीबी

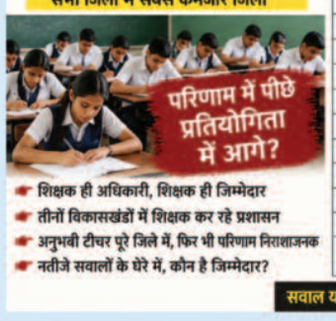

छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026: 10वीं बनाम 12वीं (तुलनात्मक चार्ट)

जिला	10वीं रैंक	10वीं %	12वीं रैंक	12वीं %	प्रदर्शन विश्लेषण
कोरिया	5	93.02	1	95.64	12वीं में जबरदस्त उछाल
बीजापुर	1	96.06	2	95.03	दोनों में लगातार टॉप
कांकेर	3	93.68	3	93.75	स्थिर उत्कृष्ट प्रदर्शन
जशपुर	4	93.29	4	93.32	संतुलित रिजल्ट
नारायणपुर	2	94.80	12	86.92	12वीं में गिरावट
रायपुर	27	71.05	15	84.79	12वीं में सुधार, पर कमजोर स्थिति
बिलासपुर	30	65.30	27	79.19	दोनों में कमजोर प्रदर्शन
दुर्ग	31	63.12	29	77.91	शिक्षा हब, लेकिन निचले स्तर पर
सरगुजा	16	83.09	24	80.56	गिरावट
सूरजपुर	17	82.75	13	86.46	सुधार दिखा
रायगढ़	18	80.06	19	83.45	मध्यम प्रदर्शन
महासमुंद	19	79.35	22	80.89	हल्की गिरावट
कोरबा	22	77.58	18	83.48	सुधार
धमतरी	23	76.18	17	84.18	अच्छा सुधार
बालोद	29	65.94	30	77.79	कमजोर
सक्ति	28	68.78	31	72.07	लगातार गिरावट
जांजगीर-चांपा	32	59.90	32	65.73	निचले स्तर पर स्थिर
MCB	33	59.12	33	62.40	सबसे कमजोर जिला

सवाल यही: शिक्षक अफसर बने, लेकिन नतीजे क्यों हुए फेल? | जिला प्रशासन के लिए गंभीर चिंतन का विषय

-संवाददाता-
एमसीबी,02 मई 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित बोर्ड परीक्षा परिणामों ने इस बार एक कड़वी सच्चाई उजागर कर दी है,नवगठित मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिला, जो प्रशासनिक रूप से नया और उम्मीदों से भरा हुआ माना जा रहा था,शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर खड़ा नजर आया है,यह स्थिति सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है,बल्कि पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है,खास बात यह है कि जिले में शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद शिक्षकों के कंधों पर है वे शिक्षक ही हैं, और वही अधिकारी भी, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब शिक्षक ही व्यवस्था चला रहे हैं, तो परिणाम इतने निराशाजनक क्यों हैं?

शिक्षक ही अधिकारी की व्यवस्था या प्रयोग?

एमसीबी जिले की शिक्षा व्यवस्था का सबसे अनोखा पहलू यही है कि यहां शिक्षकों को ही प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जिला शिक्षा कार्यालय से लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी और सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी तक के पदों पर शिक्षक कार्य कर रहे हैं, यानी जो शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए थे,वही अब कार्यालयीन कार्य, नियंत्रण,निर्देशन और पूरी शिक्षा व्यवस्था का संचालन भी संभाल रहे हैं,सिद्धांत रूप में यह व्यवस्था व्यावहारिक लग सकती है,क्योंकि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर समझते हैं लेकिन व्यवहार में यही व्यवस्था अब सवालों के घेरे में है।

परिणामों की हकीकत...आंकड़े बोले...व्यवस्था चुप रही...

बोर्ड परीक्षा परिणामों का विश्लेषण यह साफ बताता है कि एमसीबी जिला अन्य जिलों की तुलना में काफी पीछे रह गया है, यह सिर्फ अंतिम स्थान की बात नहीं है, बल्कि प्रतिशत के स्तर पर भी जिले का प्रदर्शन अन्य जिलों से काफी नीचे है। यह अंतर इतना अधिक है कि इसे सामान्य उतार-चढ़ाव नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह एक गंभीर संरचनात्मक समस्या की ओर इशारा करता है, यह स्थिति उस जिले के लिए और भी चिंताजनक हो जाती है, जहां शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नए प्रयोग किए जा रहे थे।

सबसे बड़ा सवाल...जिम्मेदारी किसकी?

इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल जिम्मेदारी का है, क्या यह परिणाम शिक्षकों की अक्षमता को दर्शाता है, या फिर यह व्यवस्था की खामी है जहां एक ही व्यक्ति पर दोहरी जिम्मेदारी डाल दी गई? जब शिक्षक को पढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक काम भी करना पड़े, तो स्वाभाविक है कि दोनों कार्यों में संतुलन बिगड़ सकता है,लेकिन यह भी उतना ही सच है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य पढ़ाना है,और अगर वही प्रभावित हो रहा है, तो जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता।

दक्षता पर सवाल अनुभव के बावजूद परिणाम खराब क्यों?

एमसीबी जिले में अनुभवी शिक्षकों की कमी नहीं है। कई शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं और उन्हें शिक्षा प्रणाली की गहरी समझ है, इसके बावजूद अगर परिणाम इतने कमजोर आते हैं,तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि समस्या कहां है, क्या शिक्षक अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी से भटक गए हैं? या फिर प्रशासनिक जिम्मेदारियों ने उनकी शिक्षण क्षमता को प्रभावित कर दिया है? यह सवाल सिर्फ शिक्षकों पर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर लागू होता है।

व्यंग्यात्मक नजरिया में पढ़ाई कम,नेतागिरी ज्यादा?

अगर इस पूरे परिदृश्य को व्यंग्यात्मक रूप में देखा जाए,तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है एमसीबी में शिक्षक अब सिर्फ पढ़ाते नहीं,फाइल भी चलाते हैं, मीटिंग भी करते हैं, और शायद इसी बीच पढ़ाई कहीं पीछे छूट जाती है,यह व्यंग्य भले हल्का लगे,लेकिन इसके पीछे की सच्चाई गंभीर है, स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी सामने आती रही है कि शासकीय स्कूलों में शिक्षण से ज्यादा अन्य गतिविधियों और 'नेतागिरी' पर ध्यान दिया जा रहा है,अगर यह धारणा सही है,तो यह स्थिति शिक्षा के लिए बेहद खतरनाक है।

जिला प्रशासन के लिए चेतावनी अब भी समय है-एमसीबी जिले का यह परिणाम केवल एक साल की असफलता नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया,तो स्थिति और बिगड़ सकती है, जिला प्रशासन को यह गंभीरता से विचार करना होगा कि क्या शिक्षकों को प्रशासनिक जिम्मेदारी देना सही निर्णय था? क्या इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है?अगर हां,तो इस मॉडल में बदलाव जरूरी है।

तुलनात्मक स्थिति: बाकी जिले आगे, एमसीबी पीछे-अन्य जिलों के मुकाबले एमसीबी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है,यह अंतर केवल प्रतिशत का नहीं,बल्कि गुणवत्ता का भी है। जहां अन्य जिले सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं,वहीं एमसीबी पीछे खड़ा नजर आ रहा है,यह स्थिति नवगठित जिले की छवि को भी प्रभावित करती है।

सुधार की जरूरत या बहानेबाजी? एमसीबी जिले के बोर्ड परीक्षा परिणामों ने यह साफ कर दिया है कि शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं बड़ी खामी है,अब सवाल यह नहीं है कि गलती किसकी है, बल्कि यह है कि सुधार कैसे होगा, अगर जिम्मेदारी तय नहीं की गई और व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया,तो आने वाले वर्षों में भी यही स्थिति बनी रह सकती है।

अंतिम सवाल : क्या यही है लक्ष्य? क्या एमसीबी जिले का लक्ष्य यही है कि वह परिणामों में पीछे रहे और सिर्फ व्यवस्थाओं के प्रयोग करता रहे? या फिर अब समय आ गया है कि शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए, जिम्मेदारियां स्पष्ट की जाएं और बच्चों के भविष्य को केंद्र में रखकर निर्णय लिए जाएं? क्योंकि अंततः सवाल केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की तैयारियां तेज

संकल्प भवन में जिला स्तरीय कार्यशाला पर मंथन,दायित्व निर्धारित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 मई 2026
(घटती-घटना)।

संकल्प भवन स्थित भाजपा कार्यालय में मासिक बैठक के साथ आगामी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यशाला की रूपरेखा, विषय-वस्तु,व्यवस्थाएं और सफल संचालन के लिए दायित्वों का विस्तार से निर्धारण किया गया। उद्देश्य कार्यशाला को सुव्यवस्थित,अनुशासित और प्रभावशाली तरीके से संपन्न कर संगठन को और मजबूत बनाना रहा। बैठक

को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को ग्रामीण विकास से जोड़ते हुए संगठन को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रशिक्षण महाअभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए अनुशासन और एकता पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने छत्तीसगढ़ सरकार के 'सुशासन तिहार 2026' की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में जन शिकायतों का त्वरित निवारण किया जाएगा तथा पात्र हितग्राहियों को तत्काल लाभ दिलाने के साथ सभी मामलों का एक माह के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशिक्षण महाअभियान के जिला प्रभारी अम्बिकेश केशरी ने कहा कि यह अभियान संगठन के आधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रशिक्षण सत्रों में पूर्ण उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया, ताकि एकात्म मानववाद के सिद्धांतों का व्यापक प्रसार हो सके। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने किया, जबकि महामंत्री अरुणा सिंह ने आभार व्यक्त किया।

नम हवाओं से बदला मौसम आंधी-बूंदाबांदी से गर्मी से राहत

40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी,तापमान में उतार-चढ़ाव जारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 मई 2026
(घटती-घटना)।

बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के असर से शनिवार को शहर सहित सरगुजा जिले में मौसम का मिजाज बदला रहा। दोपहर बाद तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। हालांकि तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री से गिरकर 33.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वहीं शनिवार को इसमें करीब 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले कुछ दिनों से तापमान 40 से 41 डिग्री के बीच बना हुआ था।

दोपहर बाद बदल रहा मौसम : मौसम वैज्ञानिक एस.के. मंडल ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण उत्तरी छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। दोपहर तक तेज धूप रहती है,लेकिन इसके बाद अचानक घने बादल छा जाते हैं और तेज हवा के साथ हल्की बारिश होती है।

तेज आंधी से नुकसान : शनिवार को जिले के कई हिस्सों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली। इसके चलते लखनपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में पेड़ उखडने और बिजली तार टूटने की खबरें सामने आई हैं।

एक सप्ताह तक असर संभव : मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं का असर अगले एक-दो दिनों तक बना रह सकता है।

इसके बाद 4 मई के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर 6 से 7 मई तक देखने को मिल सकता है।

सीतापुर सामूहिक दुष्कर्म मामला: पीड़ितों से मिले भाजपा पदाधिकारी,दोषियों को कड़ी सजा की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 मई 2026
(घटती-घटना)।

सीतापुर थाना क्षेत्र में अप्रैल 2025 में शादी समारोह में शामिल होने गई युवतियों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने पूरे सरगुजा क्षेत्र को झकझोर दिया है। घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। भाजपा सरगुजा के जिला महामंत्री अरुणा सिंह, अजजा मोर्चा जिलाध्यक्ष बिंदेश्वरी लाल पैकरा एवं महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शुभांगी बिहाडे सहित अन्य

पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान अरुणा सिंह ने घटना को बेहद निंदनीय और शर्मनाक बताते हुए कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि समाज में सख्त संदेश जाए। उन्होंने बताया कि भाजपा विधि प्रकोष्ठ भी इस मामले में सक्रिय है और अधिवक्ताओं ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया है। पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पार्टी पीड़ितों के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राजापुर भगत सिंह, महामंत्री सुदर्शन सोनी, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष दुर्गावती कश्यप, मैनपाट की बबली एवं अजजा मोर्चा के लहरूराम सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

विशेष लोक अदालत में शामिल होने 31 मई तक भरे जाएंगे आवेदन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 मई 2026
(घटती-घटना)।

जिला विधिक सेवा प्राधिकारण अम्बिकापुर के सचिव ने बताया कि न्याय को सरल एवं सुलभ तरीक से घर-घर तक पहुंचाने तथा आपसी सहभागिता और सहमति से न्याय की भावना को मूर्त रूप देने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह 2026 का आयोजन 21 अप्रैल 2026 से आरम्भ किया गया। जिसके अंतर्गत 21, 22 तथा 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।

द्वितीय अपील की सुनवाई अब कलेक्टर न्यायालय में,पक्षकारों को मिलेगी बड़ी सुविधा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 मई 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन,विधि एवं विधायी कार्य विभाग,मंत्रालय महानदी भवन,नवा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 28 अप्रैल 2026 में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में संशोधन किया गया है। यह संशोधन छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2026 के तहत लागू किया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार संहिता की धारा 44 उपधारा (2) के उपखण्ड (क) के स्थान पर नवीन प्रावधान प्रतिस्थापित किया गया है। इस संशोधन के फलस्वरूप अब धारा 44(2) के अंतर्गत द्वितीय अपील की सुनवाई का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रदान किया गया है। नवीन व्यवस्था लागू होने के बाद अग्रेत्तर सुनवाई हेतु कुल 2601 द्वितीय अपील प्रकरणों को संबंधित जिला कलेक्टर न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

नीट-यूजी 2026 3 मई 2026 को आयोजित होगी परीक्षा

अम्बिकापुर के 12 केंद्रों में शामिल होंगे 4939 परीक्षार्थी जिला प्रशासन ने तैयारियां की पूर्ण

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 मई 2026
(घटती-घटना)।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2026 के सफल और पारदर्शी आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां पूरी कर ली है। आगामी 3 मई 2026 को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए अम्बिकापुर शहर में कुल 12 केंद्र निर्धारित किए गए हैं,जहाँ 4939 परीक्षार्थी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक एक ही पाली में संपन्न होगी।

समय का विशेष ध्यानरू 1:30 बजे के बाद प्रवेश प्रतिबंधित : परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु समय-सारणी का कड़ाई से पालन किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के गेट सुबह 11:00 बजे खोल दिए जाएंगे ताकि सघन तलाशी की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। पारंपरिक या धार्मिक पोशाक पहनने वाले अभ्यर्थियों को दोपहर 12: 30 बजे तक रिपोर्ट करना अनिवार्य है। सभी परीक्षार्थियों को दोपहर 1:15 बजे तक अपनी सीट ग्रहण करनी होगी। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी स्थिति में केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थियों को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लाना अनिवार्य है, जिनके बिना प्रवेश वर्जित होगा नीट 2026 एडमिट कार्ड का स्पष्ट कलर प्रिंटआउट। पासपोर्ट साइज फोटो और प्रोफॉर्मा पर चिपकी हुई पोस्टकार्ड साइज फोटो। मूल पहचान पत्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा।

इश्तहार

मैं राम अवतार आ. श्री कुन्तेराम निवासी ग्राम खालपारा कतकालो तह.दरिमा जिला सरगुजा छ.ग. कि यह ईश्तहार कराना चाहता हूं मेरा आधार नं-3426 01447325 है में नाम एवं फोटो के साथ बना था, जिसका अपडेट कराये जाने पर आधार कार्ड में मेरा नाम रामा अवतार अंकित है जो गलत है गलत नाम हटा कर सही नाम दर्ज किया जाये जिसके संबंध में ईश्तहार करा रहा हूं, जिस किसी को आपत्ति हो वह ईश्तहार दिनांक 15 दिवस के अन्दर अनुविभागीय अधिकारी अम्बिकापुर के समक्ष अपना आपत्ति दर्ज करा सकता है। बाद में आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
अम्बिकापुर
दिनांक - 2/05/2026

आवेदक
राम अवतार
निवासी ग्राम खालपारा कतकालो तह.दरिमा जिला सरगुजा छ.ग.

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.
रा0प्र0क्र0 /20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रमोद कुमार सिंह आ0 स्व0 राजेन्द्र बहादुर सिंह जाति, निवासी चोपड़ा कॉलोनी अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - देवीगंज रोड़, शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 512 रकबा 0.22 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 04/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक- 17/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील
नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी सूरजपुर,जिला-सूरजपुर,छ0ग0
रा0प्र0क्र0 .....

ईश्तहार

आगामी तिथि 29/05/2026
इस सार्वजनिक ईश्तहार के जरिये सर्व साधारण आम जनता/संस्था/विभाग को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक विजय शंकर आ0 स्व. भीमसेन साहू, उम्र लगभग 55 वर्ष, जाति तेली, निवासी वार्ड क्र 06 सेन्ट्रल बैंक गली भैयाथान रोड सूरजपुर तहसील व जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदक के पिता स्व. भीमसेन पिता गुरूभाली के नाम पर नगर सूरजपुर में नजूल भूमि प्लाट नम्बर 1878/2893/1 रकबा 2178 वर्गफुट भूमि स्थित है। स्व. भीमसेन की मृत्यु दिनांक 03/02/2024 को हो जाने से उनका नाम विलोपित कर वषवृक्ष अनुसार फौती नामांतरण दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। जो इस न्यायालय में विचाराधीन लंबित है ।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग को कोई दावा/आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक/लीगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा/आपत्ति दिनांक 09/05/2026 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 29/04 / 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया ।

सील
नजूल अधिकारी
,सूरजपुर

न्यायालय लिंक कोर्ट देवनगर तहसील रामानुजनगर,जिला-सूरजपुर,छ0ग0

ईश्तहार

रा0प्र0क्र0...ब 121/2021-22-2026

ग्राम परसापारा के आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मान साय राजवाड़े आ0 स्व0 प्रेम साय जाति रजवार निवासी ग्राम परसापारा लिंक कोर्ट देवनगर तहसील सामनुजनगर जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदक आवेदक अपने माता स्व0 रजमेन बाई का विलम्ब मृत्यू प्रमाण पत्र पंजीयन कराने बावत् अनुलब्धता प्रमाण पत्र मय अन्य सहायक दास्तावेज के साथ न्यायालय में आवेदन पत्र पेश किया गया है । मृत्यु दिनांक 02/01/2010

अतः उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वंम अथवा किसी विविध प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 12/05/2026 को न्यायालयीन समयवधि में उपस्थित कर दावा आपत्ति पेश कर सकतें है । उसके पयचात दावा आपत्ति में कोई विचार नही किया जायेगा।

आज दिनांक 28/04/2026 को न्यायलीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया ।

नायब तहसीलदार
लिंक कोर्ट देवनगर
जिला-सूरजपुर
सील

थाने बने दुकान, कानून का हुआ सौदा...

सरगुजा में आईजी के भरोसे चल रही व्यवस्था

थाने नहीं, सौदेबाजी के अड्डे

नीचे सेटिंग, ऊपर एक्शन

गांजा पकड़कर छोड़ दिया

अपराधी आजाद, कानून बेबस

सरगुजा संभाग में कानून की 'रिटेल दुकान' और आईजी की मजबूर कार्रवाई... भरोसे का संकट और कार्रवाई का केंद्रीकरण

-रवि सिंह-

कोरिया,02 मई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग में कानून-व्यवस्था की जो तस्वीर उभर रही है,वह सामान्य प्रशासनिक ढांचे से अलग एक विचित्र और चिंताजनक परिदृश्य पेश करती है, यहां समस्या सिर्फ अपराध की नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी समस्या है,कार्रवाई का अभाव, और उससे भी आगे विश्वास का टूटना, आम नागरिक की उम्मीद होती है कि थाना उसका पहला न्यायिक दरवाजा होगा, जहां उसकी शिकायत सुनी जाएगी और कार्रवाई होगी, लेकिन अब हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि लोगों को थाने से ज्यादा भरोसा सीधे आईजी कार्यालय पर होने लगा है,यह स्थिति किसी एक घटना का परिणाम नहीं,बल्कि लगातार सामने आ रही घटनाओं का सिलसिला है,जहां कार्रवाई तब होती है जब मामला ऊपर तक पहुंचता है,यानी सिस्टम खुद से नहीं,बल्कि दबाव से चलता दिख रहा है। कोरिया जिले के पटना थाना का मामला इस पूरी व्यवस्था की असल तस्वीर सामने रखता है, दिनांक 24 अप्रैल 2026 को पुलिस ने एक युवक को तीन पैकेट गांजा के साथ पकड़ा, आरोपी को थाने लाया गया,लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी वैधानिक कार्रवाई के शाम को छोड़ दिया गया,यह कोई छोटी चूक नहीं थी,यह सीधा कानून की प्रक्रिया को नजरअंदाज करने का मामला था, जब यह जानकारी उच्च स्तर तक पहुंची,तब जाकर कार्रवाई हुई,पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) ने इस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों एएसआई इन्द्रजीत सिंह,आरक्षक अमित भारद्वाज और धन सिंह मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया,यानी सवाल यह है कि अगर मामला ऊपर तक नहीं पहुंचता,तो क्या आरोपी ऐसे ही क्रसम्मानपूर्वक विदाक्र कर दिया जाता?

आईजी की सख्ती से व्यवस्था चल रही है या संभाली जा रही है?

इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ दिखाई देती है आईजी स्तर पर सक्रियता और सख्ती,आईजी द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया,संबंधित कर्मचारियों को निलंबित किया गया,विभागीय जांच के आदेश दिए गए,7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई, यह दर्शाता है कि शीर्ष स्तर पर जवाबदेही की भावना है,लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है क्या हर बार व्यवस्था को क्रऊपर सेक्र ही चलाना पड़ेगा? अगर हर छोटी-बड़ी कार्रवाई के लिए आईजी को हस्तक्षेप करना पड़े,तो जिला स्तर की पूरी प्रशासनिक संरचना सिर्फ औपचारिक बनकर रह जाती है।

सूरजपुर का जुआ कनेक्शन...खबर छपे,तब जागे जिम्मेदार

सूरजपुर जिले में जुए का मामला भी कुछ इसी पैटर्न पर चलता नजर आया,स्थानीय स्तर पर जुए का संचालन लंबे समय तक चलता रहा,लेकिन कार्रवाई तब हुई जब लगातार खबरें प्रकाशित हुईं और मामला आईजी तक पहुंचा,इसके बाद चुनिंदा कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई,लेकिन यह कार्रवाई भी स्वतः नहीं बल्कि प्रेरित थी,यानी स्थिति यह है कि जब तक मामला सुर्खियों में नहीं आता,तब तक सिस्टम नींद में रहता है।

मनेन्द्रगढ़ और अन्य थाने जहां 'दुकानदारी मॉडल' की चर्चा

सरगुजा संभाग के अन्य थानों,विशेषकर मनेन्द्रगढ़, को लेकर भी इसी तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं,स्थानीय लोगों के बीच यह धारणा बनती जा रही है कि थाने अब कानून लागू करने की जगह समझौता केंद्र बन गए हैं जहां शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों के लिए रेट तय होता है,और कार्रवाई परिस्थितियों के हिसाब से क्रमैनेजक्र की जाती है यह धारणा कितनी सही है, यह जांच का विषय हो सकता है लेकिन यह धारणा बनना ही अपने आप में एक गंभीर संकेत है।

जनता की मानसिकता-थाने से भरोसा खत्म,आईजी ही विकल्प

अब आम नागरिक की सोच में भी बदलाव साफ दिख रहा है,पहले लोग थाने में शिकायत करते थे,अब लोग सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं,यह बदलाव प्रशासनिक असंतुलन को दर्शाता है, जब सिस्टम का पहला स्तर कमजोर पड़ता है,तो पूरा ढांचा असंतुलित हो जाता है।

व्यंग्यात्मक सच्चाये है की 'कानून' नहीं,'ऑफर' चल रहा है...

अगर इस पूरे परिदृश्य को व्यंग्य में देखें, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है सरगुजा संभाग के कुछ थानों में अब नया सिस्टम लागू हो गया है पकड़ो भी, छोड़ो भीज्बस शर्तें लागू! यह व्यंग्य भले हल्का लगे, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बेहद गंभीर है।

एसपी स्तर पर सवालः नियंत्रण क्यों कमजोर?

पूरे घटनाक्रम में जिला पुलिस अधीक्षकों (एसपी) की भूमिका भी सवालों के घेरे में आती है, क्या उन्हें इन गतिविधियों की जानकारी नहीं होती? अगर होती है,तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? और अगर नहीं होती,तो निगरानी तंत्र कहां है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आईजी का दखल अंतिम उपाय होना चाहिए, न कि नियमित प्रक्रिया।

सुधार की जरूरत या स्थिति की स्वीकृति?

सरगुजा संभाग की वर्तमान स्थिति यह संकेत देती है कि अब सुधार की आवश्यकता केवल औपचारिक नहीं, बल्कि वास्तविक है,आईजी स्तर पर हो रही कार्रवाई यह दिखाती है कि इच्छाशक्ति मौजूद है,लेकिन जब तक नीचे का ढांचा खुद जिम्मेदारी नहीं लेगा,तब तक यह सुधार अधूरा रहेगा,जरूरत इस बात की है कि थाने फिर से वही बनें,जहां आम आदमी बिना डर और संदेह के जा सके। जहां कानून प्रक्रिया के अनुसार चले,न कि परिस्थितियों के अनुसार,अंततः सवाल यही है कि क्या यह व्यवस्था खुद को सुधारने के लिए तैयार है,या फिर 'दुकानदारी' का यह मॉडल ही धीरे-धीरे नया सामान्य बन जाएगा।

अंत में सवाल वही...

क्या सरगुजा संभाग में कानून अपनी जगह पर लौटेगा,

या फिर 'दुकानदारी मॉडल' ही नया सिस्टम बन जाएगा?

प्रशासनिक ढांचा बनाम जमीनी हकीकत

कागजों में नियम स्पष्ट हैं और जिम्मेदारियां तय हैं, लेकिन जमीन पर उनका पालन एक समान नहीं दिखता। कहीं सख्ती है,तो कहीं ढीलापन,कहीं कार्रवाई तुरंत होती है, तो कहीं मामला दबा दिया जाता है,यह असमानता ही पूरे सिस्टम को कमजोर बनाती है।

समाधान क्या है?

अगर स्थिति को सुधारना है, तो थाने स्तर पर जवाबदेही तय करनी होगी, एसपी स्तर पर निगरानी मजबूत करनी होगी,शिकायत प्रणाली को पारदर्शी बनाना होगा और सबसे जरूरी–कार्रवाई को प्रतिक्रिया नहीं,प्रक्रिया बनाना होगा।

अवैध शराब पर शिकंजा,सूरजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई,तस्कर गिरफ्तार

-संवाददाता-

सूरजपुर,02 मई 2026 (घटती-घटना)।

अंतरराष्ट्रीय जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए पुलिस ने शराब तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल कर दिया,सूरजपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अंग्रेजी शराब और परिवहन में प्रयुक्त कार जब्त की है। चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश,घेराबंदी कर पकड़ा गया- पुलिस को यह सफलता 30 अप्रैल 2026 को उस समय मिली, जब थाना रमकोला क्षेत्र में नियमित वाहन चेकिंग की जा रही थी,इसी दौरान एक संदिग्ध कार (क्रमांक CG 15 EK 0367) ग्राम दुलदुली की ओर से आती दिखाई दी। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर चालक वाहन लेकर भागने लगा, स्थिति को भांपते हुए पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर वाहन को ग्राम धुरिया के पास रोक लिया।

कार की डिक्की से मिली शराब की खेप

वाहन चालक की पहचान संजय कुमार (उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम दुलदुली) के रूप में हुई, पूछताछ के दौरान जब कार की डिक्की की तलाशी ली गई,तो उसमें सफेद बोरे में भरी अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद हुईं, जांच में पाया गया कि कुल 100 नग शराब का परिवहन किया जा रहा था। इसी दौरान आरोपी ने एक कार्टून जमीन पर पटक दिया,जिससे 16 नग शराब की बोतलें टूटकर नष्ट हो गईं। शेष 84 नग अंग्रेजी शराब पुलिस ने जब्त कर ली।

10 हजार से अधिक की शराब जब्त, कोई वैध दस्तावेज नहीं

बरामद 84 नग गोवा अंग्रेजी व्हिस्की की कीमत लगभग 10,080 रुपये आंकी गई है। आरोपी से शराब के परिवहन, बिक्री या भंडारण से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज

मामले में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 11/2026 के तहत छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही शराब और परिवहन में प्रयुक्त कार को जब्त किया गया है।

पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी रमकोला हीरालाल साहू के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक जगमंडल लकड़ा,आरक्षक सोहन नेताम, मोतीलाल यादव, सैनिक रामाशंकर एवं रामोधार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

लगातार जारी है अभियान

जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अवैध गतिविधियों के विरुद्ध पुलिस का अभियान लगातार जारी है, पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शराब तस्करी सहित किसी भी गैरकानूनी कार्य में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

मनेन्द्रगढ़ में वन विभाग की फिल्मी कार्रवाई

पीछा,घेराबंदी और आरा मिल में पकड़ी गई अवैध लकड़ी से लदी गाड़ी

तस्करों के खिलाफ एक्शन,लेकिन कहानी में कई मोड़

-संवाददाता-

मनेन्द्रगढ़,02 मई 2026 (घटती-घटना)।

मनेन्द्रगढ़ में अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ वन विभाग की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसने न सिर्फ विभाग की सक्रियता को दिखाया बल्कि कई ऐसे सवाल भी खड़े कर दिए हैं जो इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना देते हैं, मुखबिर की सटीक सूचना पर शुरू हुई यह कार्रवाई किसी फिल्मी सीन से कम नहीं रही तेज रफ्तार पीछा,घेराबंदी,और आखिरकार आरा मिल के भीतर पकड़ी गई संदिग्ध गाड़ी,हालांकि,इस कार्रवाई के बीच आरोपी चालक का फरार हो जाना और कुछ अहम पहलुओं पर अस्पष्टता,इस पूरे मामले को सिर्फ एक सफलता नहीं बल्कि अधूरी कहानी भी बना देता है।

सूचना से कार्रवाई तक कैसे शुरू हुआ पूरा ऑपरेशन

रविवार 5 अप्रैल 2026 को वन विभाग को सूचना मिली कि क्षेत्र में अवैध लकड़ी का परिवहन किया जा रहा है,सूचना मिलते ही विभाग की टीम हरकत में आई और वनमंडल मार्ग पर संदिग्ध वाहन की तलाश शुरू की गई,कुछ ही देर में एक संदिग्ध वाहन नजर आया, जिसके बाद विभागीय टीम ने उसका पीछा शुरू कर दिया,जैसे-जैसे पीछा तेज होता गया,चालक पर दबाव बढ़ता गया,खुद को घिरता देख चालक ने गाड़ी को सीधे सुरजीत वुड प्रोडक्ट्स नामक

आरा मिल के अंदर घुसा दिया, मानो वहां उसे सुरक्षित पनाह मिल जाएगी, लेकिन वन विभाग की टीम ने मौके पर तेजी दिखाते हुए वाहन को घेर लिया, घिरते ही चालक ने चाबी फेंकी और मौके से फरार हो गया।

बरामदगी : सागौन और शीशम की लकड़ियों से भरी गाड़ी

जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में कीमती लकड़ी पाई गई, बरामद लकड़ियों में 11 नग सागौन और 2 नग शीशम की लकड़ियां शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 70 हजार रुपये बताई जा रही है, यह बरामदगी इस बात की पुष्टि करती है कि क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्करी का नेटवर्क सक्रिय है और यह कोई छोटी घटना नहीं बल्कि एक संगठित गतिविधि का हिस्सा हो सकता है।

कानूनी कार्रवाईः प्रकरण दर्ज,वाहन राजसात की तैयारी

वन विभाग ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पीओआर प्रकरण क्रमांक 19093 दर्ज कर लिया है। साथ ही, जब्त किए गए वाहन को राजसात करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, बताया जा रहा है कि वाहन राजू कुरैशी नामक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है, जो कथित रूप से कबाड़ व्यवसाय से जुड़ा हुआ है,हालांकि, इस मामले में उसकी भूमिका कितनी गहरी है, यह अभी जांच का विषय है।

फिल्मी कार्रवाई के बीच उठते सवाल और कहानी अभी अधूरी है...

वन विभाग की इस कार्रवाई की सराहना हो रही है,लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं जो पूरे मामले की गंभीरता को और बढ़ा देते हैं,सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस आरा मिल के अंदर गाड़ी घुसी,वहां लगे सीसीटीव कैमरों का डीवीआर अब तक जब्त क्यों नहीं किया गया? अगर यह कदम उठाया जाता,तो चालक की पहचान और पूरे नेटवर्क की जानकारी आसानी से सामने आ सकती थी, दूसरा बड़ा सवाल चालक की पहचान को लेकर है, अब तक उसका नाम और विवरण सामने नहीं आना जांच की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या वाहन मालिक ही इस पूरे अवैध कारोबार का मुख्य सूत्रधार है,या इसके पीछे कोई बड़ा लकड़ी माफिया काम कर रहा है।

संभावित नेटवर्क क्या यह सिर्फ एक गाड़ी का मामला है?

इस घटना को केवल एक वाहन तक सीमित मानना जल्दबाजी होगी,जिस तरह से वाहन आरा मिल तक पहुंचा और वहां घुसा,वह इस बात की ओर इशारा करता है कि तस्करी का यह नेटवर्क पहले से तैयार और संगठित हो सकता है,अगर जांच गहराई से की जाती है,तो संभव है कि इस मामले से जुड़े और भी बड़े नाम सामने आएं।

कार्रवाई बड़ी,लेकिन जवाब अभी बाकी

मनेन्द्रगढ़ में वन विभाग की यह कार्रवाई निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है, फिल्मी अंदाज में की गई इस घेराबंदी ने यह दिखाया कि विभाग सतर्क और सक्रिय है, लेकिन इस सफलता के साथ-साथ कई ऐसे सवाल भी खड़े हुए हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है,अब देखना यह होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्या यह मामला केवल वाहन जब्ती और लकड़ी बरामदगी तक सीमित रह जाएगा,या फिर इसके पीछे छिपे पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा, क्योंकि अगर इस बार भी जांच अधूरी रह गई, तो यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी।

धान खरीदी में 'गायब स्टॉक' का खेल: सूरजपुर में कागजों की फसल,गोदामों में भराई और प्रशासन की खामोशी

-शमरोज खान-
सूरजपुर,02 मई 2026
(घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले में धान खरीदी का मौसम खत्म हुए करीब चार महीने बीत चुके हैं,लेकिन धान का आना अभी भी जारी है,यह सुनने में जितना सामान्य लगता है,असल में उतना ही गंभीर सवाल खड़ा करता है,जब किसानों के पास अब धान बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, जब खरीदी की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुकी है,तब समितियों में पहुंच रहा यह नया धान आखिर कहां से आ रहा है? यहीं से एक ऐसे खेल की परतें खुलती हैं,जो सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित घोटाले की कहानी कहता है, यह कहानी कागजों में खरीदे गए धान की है,जो जमीन पर कभी था ही नहीं,और अब उसी क्रगायब धानक्र को छुपाने के लिए बाहर से सस्ता धान लाकर गोदामों में भरा जा रहा है।

शिवप्रसादनगर जहां से उठी गड़बड़ी की पहली आवाज

धान खरीदी के दौरान शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र का नाम लगातार चर्चा में रहा, यहां से अनियमितताओं की खबरें लगातार सामने आती रहीं, कागजों में खरीदी और जमीन पर वास्तविकता के बीच का अंतर धीरे-धीरे उजागर होता गया, कुछ समितियों पर कार्रवाई भी हुई, जांच के आदेश भी दिए गए, लेकिन अंत में परिणाम वही रहा–शून्य, इससे यह साफ हो गया कि समस्या सिर्फ एक केंद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में कहीं न कहीं गहरी जड़ें जमा चुकी है।

खरीदी के समय का खेल कागजों में धान,खातों में पैसा

धान खरीदी के दौरान जो सबसे बड़ा खेल खेला गया, वह था क्रपहले एंट्री,फिर भुगतान,लेकिन धान गायबक्र का मॉडल, कई किसानों के नाम पर धान खरीदी दिखा दी गई,उनके खातों में पैसे डाल दिए गए,लेकिन असल में वह धान कभी समिति तक पहुंचा ही नहीं। बोरियां रजिस्टर में चढ़ती रहीं,स्टॉक बढ़ता रहा,और कागजों में सब कुछ सही दिखता रहा, यह एक ऐसा तंत्र था जिसमें कागजों पर सब कुछ वैध दिखता है, लेकिन जमीन पर वास्तविकता पूरी तरह अलग होती है।

चार महीने बाद का सच और अब शुरू हुई 'भरपाई' की कहानी

अब जब खरीदी समाप्त हो चुकी है और सिस्टम को हिसाब देना है,तब असली संकट सामने आया है,कागजों में जो धान दिखाया गया था,वह गोदामों में मौजूद नहीं है,इस कमी को छुपाने के लिए अब बाहर से सस्ता धान खरीदकर लाया जा रहा है, यह धान पिकअप वाहनों के जरिए समितियों तक पहुंचाया जा रहा है और गोदामों में भरकर रिकॉर्ड से मिलाया जा रहा है, यानी जो धान कभी था ही नहीं, उसे अब क्रलाकर दिखाया जा रहा है।

बसदेई समिति में शॉर्टेज छुपाने का जमीनी उदाहरण

बसदेई सहकारी समिति इस पूरे खेल का ताजा उदाहरण बनकर सामने आई है, यहां से जो जानकारी सामने आई है,वह बेहद चौंकाने वाली है,सूत्रों के अनुसार,देर रात पिकअप वाहनों के जरिए बाहर से धान लाकर समिति में खाली कराया जा रहा है,यह पूरा काम इस तरह से किया जा रहा है कि किसी को इसकी भनक न लगे,यह धान किसानों से खरीदा गया नहीं है,बल्कि उस कमी को छुपाने का प्रयास है जो पहले की फर्जी खरीदी से पैदा हुई थी।

कम कीमत में खरीद,ज्यादा में दिखाना मुनाफे का गणित

इस पूरे खेल का आर्थिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जब धान खरीदी के समय ?30-?31 प्रति किलो की दर से भुगतान दिखाया गया और अब वही धान 20-22 प्रति किलो में बाहर से खरीदा जा रहा है, तो प्रति क्विंटल करीब ?800 का अंतर बनता है,यह अंतर किसी सिस्टम में नहीं जाता,बल्कि सीधे उन लोगों की जेब में जाता है जो इस पूरे खेल को चला रहे हैं,यानी पहले कागजों में कमाई, फिर भरपाई के नाम पर दूसरी कमाई–एक ही घोटाले में दोहरा लाभ।

प्रशासन की चुप्पी को क्या समझे अनजान या अनदेखा?

इतने बड़े स्तर पर हो रही इस गतिविधि के बावजूद प्रशासन की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आती है, लगातार खबरें सामने आईं, स्थानीय स्तर पर चर्चा भी हुई, लेकिन ठोस कार्रवाई कहीं नजर नहीं आई, यह चुप्पी अब सवाल खड़े कर रही है कि क्या प्रशासन इस पूरे खेल से अनजान है,या जानबूझकर आंखें मूंदे बैठा है।

किसानों का नुकसान : असली हकदार पीछे छूटे

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है, जिन किसानों ने वास्तव में मेहनत करके धान उगाया,उन्हें उनका पूरा लाभ नहीं मिला। वहीं जिनके नाम पर फर्जी एंट्री की गई,वे सिर्फ कागजों में ही खरीदी का हिस्सा बनकर रह गए,इससे न सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ,बल्कि सिस्टम पर भरोसा भी कमजोर पड़ा।

व्यंग्य में छिपा सच है की खेत नहीं,फाइल में उग रहा धान

अगर इस पूरे घटनाक्रम को व्यंग्य में देखा जाए,तो तस्वीर बेहद तीखी बनती है, क्रसूरजपुर में अब धान खेत में नहीं,फाइलों में उगता है और जब हिसाब देना होता है,तो पिकअप में लादकर गोदाम में बो दिया जाता है,यह व्यंग्य सिर्फ एक पंक्ति नहीं,बल्कि पूरे सिस्टम की स्थिति का आईना है।

अंतिम सवाल : सुधार या स्थायी 'मैनेजमेंट'?

अब देखना यह है कि सूरजपुर जिला प्रशासन इस पूरे मामले को कैसे लेता है, क्या यह सिस्टम खुद को सुधारने की दिशा में कदम उठाएगा, या फिर यह क्रफर्जी खरीदी और असली कमाईक्र का खेल आगे भी जारी रहेगा? क्योंकि अगर यही स्थिति बनी रही, तो आने वाले समय में धान सिर्फ खेतों में नहीं, बल्कि फाइलों में ही उगता रहेगा—और उसका हिसाब कभी साफ नहीं हो पाएगा।

क्या होगा इस 'फाइल वाले धान' का हिसाब?

सूरजपुर जिले में धान खरीदी का यह मामला अब सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक बड़े घोटाले का संकेत बन चुका है,अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी,अगर इस बार भी कार्रवाई नहीं हुई, तो यह केवल एक घोटाले की कहानी नहीं रहेगी, बल्कि यह एक ऐसे सिस्टम की पहचान बन जाएगी जहां कागजों में सब कुछ सही होता है,लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और ही होती है।

सूरजपुर पुलिस ने 18 ग्रामों में लगाया चलित थाना, कई शिकायतों का मौके पर ही किया निराकरण

चलित थाना लगाने का मुख्य उद्देश्य जनसेवा को आसान बनाना है-डीआईजी/एसएसपी सूरजपुर

नागरिकों को साईबर अपराध से बचाव की दी गई जानकारी

शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए किया गया प्रेरित

अवैध कार्यो की सूचना पुलिस को देने की अपील

-संवाददाता-
सूरजपुर,02 मई 2026
(घटती-घटना)।

जनसेवा को आसान बनाने,आम जनता के शिकायतों का मौके पर निराकरण कर राहत पहुंचाने,साईबर अपराध से बचाव, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता,महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए अभिव्यक्ति ऐप के बारे में प्रचार-प्रसार तथा गांवों में पुलिस की सक्रिय और प्रभावी उपस्थिति एवं सूचना तंत्र को प्रभावी ढंग से विकसित करने के उद्देश्य को लेकर डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने जिले के सभी थाना-चौकी प्रभारियों को प्रत्येक गांव में चलित थाना लगाने के निर्देश दिए है।

27-28 अप्रैल 2026 को जिले के 18 ग्रामों में चलित थाना का आयोजन कर थाना-चौकी प्रभारी व पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों कहा कि पुलिस द्वारा चलित थाना लगाने का मुख्य उद्देश्य जनसेवा को आसान बनाना और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है,सेवाओं को

अवैध कार्यो की सूचना देने की अपील

चलित थाना के दौरान थाना-चौकी प्रभारी व पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को अवैध कारोबार, अवैध शराब, नशे के धंधे में लिप्त लोगों,जुआ खेलने वालों की सूचना देने की अपील किया ताकि उनके विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही की जा सके, इस दौरान जनप्रतिनिधियों, सरपंच, पंच व ग्रामवासियों के सुझाव भी लिए गए, यातायात नियमों की जानकारी देकर उसका पालन करने, घटना-दुर्घटना की सूचना फौरन देने तथा सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद कर राहवीर (गुड सेमेटेरियन) बनते हुए उन्हें तत्काल नजदीक के अस्पताल ले जाने हेतु प्रोत्साहित किया है।

जनता के करीब लाना और लोगों को अपनी छोटी-मोटी शिकायतों या समस्याओं के लिए थाने के चक्कर न काटने पड़ें,इसलिए आज वे खुद उनके गांव पहुंचे है, इस मौके पर कई ग्रामीणों के शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया है और उन्हें डिजिटल अरेस्ट, साइबर अपराध सहित सुरक्षा से जुड़े पहलुओं के प्रति जागरूक निराकरण किया है, इसके साथ ही गांव में होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध व अवैध कार्यो की सूचना तत्काल पुलिस को देने की हिदायत दिया है, पुलिस की इस अभियान से ग्रामीणों में उत्साह है और पुलिस के कार्यो में सहयोग के लिए अब वे आगे आ रहे है,इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा शासन की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।

ठगी से सावधान रहने किया जागरूक

थाना-चौकी की पुलिस के द्वारा आयोजित चलित थाना के दौरान ग्रामीणों को म्यूल अकाउंट,डिजिटल अरेस्ट के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि डिजिटल अरेस्ट एक साइबर स्कैम है,जिसमें फ़र्ज़ी सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को डरा-धमकाकर पैसे वसूले जाते हैं। यह एक तरह का ऑनलाइन ब्लैकमेल है,डिजिटल अरेस्ट में,फ़र्ज़ी अधिकारी वीडियो कॉल पर लोगों को डराते-धमकाते हैं और उन्हें गिरफ़्तारी के झूठे बहाने से डिजिटल रूप से बंधक बना लेते हैं,इस दौरान वे लोगों से लगातार वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए कहते हैं और पैसे ट्रांसफ़र करवाते रहते हैं। डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत एक मैसेज या फ़ोन कॉल के साथ होती है। फ़र्ज़ी अधिकारी,पुलिस, सीबीआई,नारकोटिक्स,आरबीआई,या दिल्ली या मुंबई पुलिस अधिकारी बनकर बात करते हैं, वे लोगों को यह बताते हैं कि उनके पैन और आधार का इस्तेमाल करके तमाम चीज़ें खरीदी गई हैं या मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। कई बार यह भी दावा किया जाता है कि वे कस्टम विभाग से बोल रहे हैं और आपके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स या प्रतिबंधित चीज़ें हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आसान भाषा में कहा जाए तो डिजिटल अरेस्ट में फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को डरा-धमकाकर उनसे बड़ी रकम वसूल कर लेते है,मौजूद ग्रामीण,महिलाओं व बच्चों को कानून की जानकारी देते हुए अपराध से बचने की समझाईश दी,वर्तमान दौर साइबर अपराध म्यूल अकाउंट,बैंक एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने तथा बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी बनकर मोबाइल से आधार कार्ड एवं एटीएम कार्ड की गोपनीय जानकारी प्राप्त कर बैंक खातों से रकम पार करने की घटित हो रही घटनाओं की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को देते हुए ठगी का शिकार होने से बचने की सलाह दी,इसी क्रम यातायात नियमों की जानकारी देते हुए उसका पालन करने की अपील की साईबर अपराध,महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों,प्राकृतिक आपदा के मामले में राहत राशि,सहित विधिक जानकारियों से अवगत कराते हुए कहा कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है,महिला सुरक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी अभिव्यक्ति ऐप के बारे में अवगत कराया। इसी क्रम में नशा न करने की समझाईश देते हुए नशे से होने वाली आर्थिक,सामाजिक एवं शारीरिक हानियों के बारे में अवगत कराया।

CMYK

राजेश खन्ना की सबसे बड़ी फ्लॉप ने अनिल कपूर के पिता को कर दिया था कंगाल, एक्टर को खुद करना पड़ा था डेब्यू

अनिल कपूर ने हाल ही में बताया कि कैसे राजेश खन्ना की एक फिल्म के फ्लॉप होने से उनके पिता, निर्माता सुरिंदर कपूर को भारी नुकसान हुआ और वे अकेले पड़ गए। इस घटना ने अनिल कपूर को अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। फिल्म इंडस्ट्री में सफलता रातोंरात बदल सकती है। अनिल कपूर ने इसे बहुत कम उम्र में ही अनुभव कर लिया था। हाल ही में एक बातचीत में, एक्टर ने बताया कि सुपरस्टार राजेश खन्ना की एक फिल्म के फ्लॉप होने का उनके पिता और निर्माता सुरिंदर कपूर पर कितना गहरा असर पड़ा था।

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी फिल्म

अनिल कपूर ने उस घटना को भी याद किया जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक्टर बनने के लिए प्रेरित किया। अनिल कपूर अक्सर अपने पिता की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की बात करते रहे हैं। एक बातचीत के दौरान उन्होंने याद किया कि कैसे उनके पिता की एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी जिसके बाद कई लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी।

बेहद अकेले पड़ गए थे अनिल कपूर के पिता

उस पल को याद करते हुए अनिल ने लिली सिंह को बताया कि उनके पिता, जो कभी लोगों से घिरे रहते थे, फिल्म की असफलता के बाद अचानक अकेले पड़ गए। अनिल ने कहा,वे दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे थे और हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने कोई नहीं आया था। सबने मानो उन्हें छोड़ दिया था, जैसे उन्हें अपना मानने से इनकार कर दिया हो। यह बहुत चौंकाने वाला थाज मैं देख सकता था कि वे बहुत कमजोर थे और शायद रो रहे थे।

पिता ने नहीं की एक्टर बनने में मदद

अनिल कपूर ने कहा कि वह अनुभव उनके मन में हमेशा के लिए बस गया। यह सिर्फ एक फिल्म के असफल होने की बात नहीं थी; बल्कि यह इस बात का भी उदाहरण था कि इंडस्ट्री में सफलता कितनी नाजुक हो सकती है। अनिल ने यह भी बताया कि निर्माता होने के बावजूद उनके पिता ने कभी उनके लिए चीजें आसान नहीं बनाईं। जब अनिल ने एक्टिंग करने की इच्छा जताई, तो सुरिंदर कपूर ने साफ कर दिया कि उन्हें अपना रास्ता खुद ही खोजना होगा। लगभग 18 या 19 साल की कम उम्र में ही अनिल ने जिम्मेदारी की भावना के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। एक्टर ने आगे कहा, मेरे पिता एक फिल्म निर्माता थे और उस समय उनकी फिल्मों के लिए लीड एक्टर मिलना मुश्किल था। इसलिए मैंने कहा,%मुझे अभिनेता बनना है। मुझे मुख्य अभिनेता बनना है। अनिल कपूर को आखिरी बार फिल्म सूबेदार में देखा गया था। ये अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है।

मिथुन की बहू से डायरेक्टर ने की थी गंदी डिमांड

टीवी शो अनुपमा फेम मदालसा शर्मा ने 19 साल की उम्र में अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के अनुभव को साझा किया है। उन्होंने बताया कि एक मशहूर निर्देशक ने उन्हें फिल्म के लिए बिकिनी में देखने की मांग की थी, जिसे उन्होंने दृढ़ता से ठुकरा दिया। टीवी शो अनुपमा में काव्या की भूमिका निभाकर मदालसा शर्मा ने पॉपुलैरिटी हासिल की थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने 19 साल की उम्र में अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस पर बात की। उन्होंने द मेल फेमिनिस्ट पॉडकास्ट से बातचीत में बताया कि एक निर्देशक ने उन्हें फिल्म के सिलसिले में बुलाया और अपने सामने बिकिनी पहनने को कहा। मदालसा ने तुरंत स्थिति को संभाला और अपनी बात पर अड़ी रहीं। इंटरव्यू में बात करते हुए मदालसा ने बताया कि कैसे एक डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पर वो बिल्कुल शॉक्ड रह गए थीं।

बिकिनी में देखना चाहता था डायरेक्टर

मदालसा ने कहा,एक बहुत ही मशहूर फिल्म निर्माता ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। उस समय मेरी उम्र लगभग 19 साल थी। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जो बिकिनी में सहज महसूस करती हो। मैंने मन ही मन सोचा कि सच कहूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हैज इसलिए मैंने हां कह दी, लेकिन फिर मैं कहानी को समझना चाहती थी। क्या यह कहानी में के लिए जरूरी है भी या फिर बिल्कुल ही अलग एंगल है? मैं 19 साल की थी, लेकिन मैं समझदार थी।

मदालसा ने दिया था करारा जवाब

एक्ट्रेस ने आगे कहा...डायेक्टर ने कहा कि वो मुझे बिकिनी में देखना चाहता था कि मैं कैमरे के सामने कम्फर्टेबल हूं कि नहीं। मैंने कहा कि अगर रोल के लिए जरूरत होगी तो मैं लहंगा, बिकिनी, साड़ी कुछ भी पहन सकती हूं लेकिन आपके सामने पहनना ये मेरे रोल की जरूरत नहीं। अगर आपको टैलेंट देखना है तो ठीक नहीं तो आपको भी पता है दरवाजा किधर है। एक्ट्रेस बोलीं कि इतना बोलकर मैं बाहर निकल गई और जानने की कोशिश भी नहीं की कि डायरेक्टर मेरे बारे में क्या सोचेगा।

अनुपमा ने निभा चुकी हैं काव्या का रोल

मदालसा को हिट टीवी शो अनुपमा में काव्या के किरदार के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। इस पारिवारिक ड्रामा सीरीज में रूपाली गांगुली के साथ उनके किरदार में कई शेड्स थे। रूपाली ने शो में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसमें एक गृहिणी रिश्तों और परिवार से जुड़े सामाजिक मानदंडों को चुनौती देती है। यह शो जियो हॉटस्टार पर आता है।

साथी लीलावती ट्रेलर रिलीज,इमोशनल फैमिली ड्रामा और रिश्तों की जटिलता ने खींचा ध्यान

फिल्म साथी लीलावती का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें भावनात्मक पारिवारिक रिश्तों और पति-पत्नी के बीच जटिल संबंधों की कहानी दिखाई गई है। ट्रेलर की शुरुआत एक भावनात्मक दृश्य से होती है, जहां अभिनेता नरेश अपनी बेटी के साथ एक दिल छू लेने वाला पल साझा करते हैं। इस किरदार को लावण्या त्रिपाठी ने निभाया है। शुरुआती दृश्य में नरेश अपनी बेटी से कहते हैं कि उन्होंने उसे 20 साल तक पाला-पोसा, लेकिन

उन वर्षों में वह उतनी खुश कभी नहीं दिखी, जितनी वह अपनी शादीशुदा जिंदगी के सिर्फ तीन वर्षों में नजर आती है। यह संवाद फिल्म के भावनात्मक आधार को मजबूत करता है और दर्शकों को कहानी से जोड़ता है। इसके बाद ट्रेलर का रुख मुख्य कहानी की ओर होता है, जो एक दंपति के बीच के जटिल और तनावपूर्ण रिश्ते पर केंद्रित है। फिल्म में पति-पत्नी के बीच की रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाया गया है, जिसमें लगातार झगड़े, गलतफहमियां और भावनात्मक दूरी प्रमुख रूप से सामने आती हैं। कहानी में तनाव तब और बढ़ जाता है जब लावण्या त्रिपाठी का किरदार अपने पति पर किसी अन्य महिला के साथ संबंध होने का शक करने लगती है। यह शक उनके रिश्ते में और अधिक दरार पैदा कर देता है और कहानी को एक गंभीर मोड़ पर ले जाता है। ट्रेलर में दिखाए गए दृश्य पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं और विश्वास की कमी से पैदा होने वाले तनाव को उजागर करते हैं। इसमें भावनात्मक उतार-चढ़ाव के साथ-साथ घरेलू जीवन की वास्तविक समस्याओं को भी दर्शाया गया है, जिससे कहानी अधिक वास्तविक और प्रभावशाली लगती है।

शोभिता धुलिपाला का नया फोटो फीचर लुक चर्चा में,क्रीम वेस्टकोट में दिखा क्लासी अंदाज़

अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला अपने नए फोटो फीचर को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। इस फोटो सीरीज़ में उनका लुक बेहद शांत, सादगीभरा और आधुनिक फैशन के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है। तस्वीरों में उनका स्टाइल एक साफ-सुथरे और सोफिस्टिकेटेड अंदाज़ को दर्शाता है, जिसमें फैशन और व्यक्तित्व का संतुलन देखने को मिलता है। इस फोटोशूट में शोभिता क्रीम रंग की स्लीवलेस वेस्टकोट में नजर आ रही हैं, जिसे खास तौर पर उनके सिल्हूट को उभारने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आउटफिट न केवल उनके लुक को संरचित और परिष्कृत बनाता है, बल्कि एक मिनिमलिस्टिक फैशन स्टेटमेंट भी पेश करता है। वेस्टकोट का कट और फिटिंग उनके पूरे व्यक्तित्व को एक एलिगेंट टच देता है, जिससे पूरा लुक बेहद संतुलित दिखाई देता है। डिज़ाइन में शामिल नाज़ुक चाइनीज़-स्टाइल बटन डिटेलिंग इस आउटफिट का एक खास आकर्षण है। यह डिटेलिंग पारंपरिक फैशन इंस्पिरेशन को आधुनिक डिजाइन सेंस के साथ जोड़ती है। छोटे-छोटे बटन और उनका सूक्ष्म उपयोग पूरे लुक में एक सॉफ्ट लेकिन प्रभावी सौंदर्य जोड़ते हैं। इस तरह की डिजाइन एलिमेंट्स आज के फैशन में क्लासिक और मॉडर्न के मेल को दर्शाते हैं, जो कई डिजाइनरों के काम में भी देखने को मिलता है।

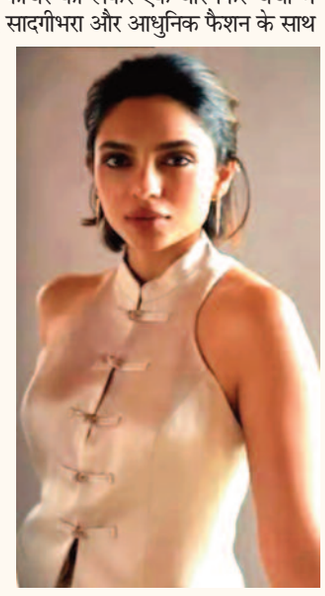

खेल समाचार

केआईएसएस यूनिवर्सिटी के 9 छात्र रग्बी प्रीमियर लीग 2026 के लिए चुने गए

भुवनेश्वर ,02 मई 2026। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यूनिवर्सिटी के कुल 9 छात्रों को, जिनमें पाँच लड़कियाँ और चार लड़के शामिल हैं, रग्बी प्रीमियर लीग 2026 के लिए चुना गया है। रग्बी प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने के लिए चुने गए नौ छात्र हैं- किशोर माझी, गणेश धंगड़ा माझी, आशीष शबर, संजय किसान, निर्मल्या राउत, तरुलता नायक, दुमुनी मारंडी, हुपी माझी और मामा नायक। जहाँ किशोर माझी को चेन्नई बुल्स टीम ने 1,25,000 रुपये में चुना, वहीं गणेश धंगड़ा माझी को बेंगलुरु ब्रेवहार्ट्स ने 90,000 रुपये में चुना है। इसी तरह, आशीष शबर मुंबई ड्रीमर्स के लिए और संजय किसान कोलकाता बंगाल टाइगर्स के लिए 50,000 रुपये में खेलेंगे। महिलाओं की श्रेणी में, निर्मल्या राउत को कोलकाता बंगाल टाइगर्स ने सबसे ज़्यादा कीमत 1,60,000 रुपये में चुना है। जहाँ तरुलता नायक 80,000 रुपये में चेन्नई बुल्स में शामिल हुई हैं, वहीं दुमुनी मारंडी दिल्ली रेड्स के लिए 60,000 रुपये में खेलेंगी, और हुपी माझी तथा मामा नायक मुंबई ड्रीमर्स के लिए 50,000 रुपये में खेलेंगी।रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन 16 से 28 जून तक गचीबोवली स्टेडियम में किया जाएगा। केआईएसएस के ये युवा खिलाड़ी देश के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए तैयार हैं। यह सिर्फ़ एक चयन नहीं है, बल्कि केआईएसएस की लंबे समय की कड़ी मेहनत, प्रशिक्षण और प्रतिभा का सफल परिणाम है। केआईएसएस आदिवासी युवाओं को राष्ट्रीय मंच पर प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी कोचों को ला रहा है। अपने गाँवों से भुवनेश्वर तक का सफ़र तय करने के बाद, इन खिलाड़ियों ने आज राष्ट्रीय मंच पर अपना नाम रोशन किया है। यह के आईआईटी और केआईएसएस के संस्थापक डॉ. अच्युत सामंत के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। इन खिलाड़ियों ने आज डॉ. सामंत से मुलाक़ात की और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने भी इन खिलाड़ियों की सफलता पर अपनी खुशी और शुभकामनाएँ व्यक्त कीं।

पाक क्रिकेट में फिर उठा 'हैंडशेक विवाद'

नई दिल्ली,02 मई 2026। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले हमेशा चर्चा में रहते हैं, और एक बार फिर दोनों टीमों के बीच हुए 'हाथ मिलाने' से जुड़े विवाद ने सुर्खियां बटोरी हैं। पिछले वर्ष एशिया कप के दौरान पहलगाम हमले के बाद बने तनावपूर्ण माहौल में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का निर्णय काफी चर्चा में रहा था। अब पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उस दिन की घटनाओं का विवरण साझा किया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सलमान अली आगा ने बताया कि टॉस से पहले उन्हें किसी भी तरह की असामान्य स्थिति की पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर टॉस के दौरान कप्तानों के बीच हाथ मिलाना, ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाना और औपचारिक बातचीत का हिस्सा होता है, लेकिन उस मैच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगा ने कहा, ÷टॉस से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां सामान्य प्रक्रियाओं की बात की गई थी। मुझे अंदाज़ा था कि माहौल पूरी तरह सामान्य नहीं होगा, लेकिन मुझे यह नहीं बताया गया था कि हाथ बिल्कुल भी नहीं मिलाए जाएंगे।÷ उन्होंने आगे बताया कि जब वे टॉस के लिए पहुंचे, तो उन्हें मैच रेफरी ने एक तरफ ले जाकर स्पष्ट रूप से कहा कि इस मैच में कप्तानों के बीच कोई हैंडशेक नहीं होगा।

भारत की वो 5 बेटियां,जो हिंदुस्तान को जिता सकती हैं टी 20 वर्ल्ड कप

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 12 जून से इंग्लैंड में शुरू होने वाला है...इस टी20 विश्व कप के लिए भारत नो अपनी टीम भी अनाउंस कर दी है...हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करने वाली हैं...

नई दिल्ली,02 मई 2026। आईसीसी महिला टी 20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। 12 जून से शुरू होने वाले इस विश्व कप में भी हरमनप्रीत कौर ही टीम की कप्तानी करती हुई नजर आएंगी। वहीं स्मृति मंधाना उपकप्तान हैं। आइये जानते हैं उन 5 भारत की बेटियों के बारे में, जो हिंदुस्तान को पहली बार महिला टी20 वर्ल्ड कप जिता सकती हैं।

हरमनप्रीत कौर

भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से टी20 विश्व कप में टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका निभा सकती हैं। उनका अनुभव भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकता है।

स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना इस महिला विश्व कप में भारतीय टीम की उपकप्तान हैं। उन्होंने महिला वनडे विश्व कप में भी भारत की जीत में अहम रोल निभाया था। इस बार इंग्लैंड में भी वह कमाल कर सकती हैं।

जेमिमा रोड्रिग्स

भारत की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स भी इस टीम का हिस्सा हैं। रोड्रिग्स ऊपर आकर अच्छे रन बनाती हैं। उन्होंने 2025 के वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 127 रन की मैच विनिंग पारी खेली थी।

राधा यादव

अनुभवी ऑलराउंडर राधा यादव इस विश्व कप में भारत के लिए मिडल ऑर्डर में आकर रन भी बना सकती हैं और विकेट भी ले सकती हैं। बतौर सीनियर खिलाड़ी राधा से भी काफी उम्मीदें होंगी।

रेणुका सिंह

तेज गेंदबाज रेणुका सिंह भी महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए अहम भूमिका निभा सकती हैं। इंग्लिश कंडीशन में रेणुका शानदार प्रदर्शन कर सकती हैं। उन्होंने भारत के लिए 63 टी20 खेले हैं और 68 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी भी अच्छी है।

जीत की लय वापस हासिल करना चाहेगी पीबीकेएस,अहमदाबाद में जीटी से सामना

अहमदाबाद,02 मई 2026। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 46वें मैच में गुजरात टाइटंस (जीटी) का सामना पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) से होगा। यह मैच रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। लीग चरण के रोमांचक होने के साथ-साथ दोनों टीमें अहम प्वाइंट्स हासिल करने पर नजरें गड़ाए हैं। पंजाब किंग्स 8 में से 6 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है। इस टीम का एक मैच बारिश के चलते रद्द भी हुआ था। फिलहाल 13 अंकों के साथ पीबीकेएस प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पायदान पर है। इस टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों में ही जबरदस्त निरंतरता दिखाई है। पिछली बार हारने के बाद यह टीम अपनी लय वापस पाना चाहेगी। इस सीजन में 7वीं जीत के साथ पंजाब किंग्स प्वाइंट्स टेबल में अपनी बादशाहत कायम करना चाहेगी। दूसरी तरफ, 9 में से 5 मैच जीतकर गुजरात टाइटंस की टीम पांचवें स्थान पर

है। जीटी ने शुरुआती 2 मैच गंवाने के बाद अगले 7 में से 5 मुकाबले अपने नाम किए हैं। जैसे-जैसे गुजरात टाइटंस वापसी की कोशिश कर रहा है और पंजाब किंग्स अपनी बादशाहत फिर से कायम करने का प्रयास कर रहा है, अहमदाबाद में होने वाला यह मैच दो बराबरी की टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है, जिनका हालिया प्रदर्शन काफी अलग रहा है। दोनों टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में कुल 7 मैच खेले गए हैं। पंजाब किंग्स ने 4 मैच अपने नाम किए, जबकि गुजरात टाइटंस को 3 मुकाबलों में जीत नसीब हुई। पंजाब किंग्स की टीमः श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बरार, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुइस, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद।

गुजरात टाइटंस की टीमः शुभमन गिल (कप्तान),साई सुदर्शन, शाहरुख खान, अनुज रावत,जोस बटलर, कुमार कुशाग्र,टॉम बैंटन,ग्लेन फिलिप्स,जेसन होल्डर,निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, साई किशोर,जयंत यादव,अरशद खान, शाहरुख खान,मानव सुथार,राशिद खान,मोहम्मद सिराज,कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा,ईशांत शर्मा,गुरनूर बराड़,अशोक शर्मा,ल्यूक वुड, पृथ्वी राज यारा।

न्यूजीलैंड क्रिकेट में दक्षिण एशियाई खिलाड़ियों का बढ़ता प्रभाव

मेलबर्न,02 मई 2026। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दक्षिण एशियाई समुदाय तेजी से बढ़ते प्रवासी समूहों में शामिल है और इसका असर क्रिकेट पर भी साफ दिखाई दे रहा है। खासकर न्यूजीलैंड क्रिकेट ने इस बदलाव से काफी फायदा उठाया है। सीमित आबादी और संसाधनों के बावजूद देश ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचानकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। न्यूजीलैंड की आबादी लगभग 5.3 मिलियन है और न्यूजीलैंड क्रिकेट के पास वित्त वर्ष 2025 के लिए लगभग 37 मिलियन डॉलर का रिजर्व और 26.9 मिलियन डॉलर की फंडिंग है। ऐसे सीमित संसाधनों के बीच भी बोर्ड ने दक्षिण एशियाई मूल के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इस लिस्ट में दीपक पटेल को शुरुआती मार्गदर्शक माना जाता है,जिन्होंने उपमहाद्वीप से आए खिलाड़ियों के लिए रास्ता खोला। उनके बाद जीतन पटेल,जीत रावल,तरुण नेथुला,रॉनी हीरा,ईश सोढ़ी,एजाज पटेल,रचिन रवींद्र और आदित्य अशोक जैसे कई खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड टीम का प्रतिनिधित्व किया।

छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट..4 जवान शहीद

इसमें डीआरजी के इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल शामिल,कांकेर-नारायणपुर बॉर्डर पर माइनिंग हटाते समय हादसा

जगदलपुर,02 मई 2026। छत्तीसगढ़ के कांकेर-नारायणपुर बॉर्डर पर शनिवार को आईईडी ब्लास्ट में 4 जवान शहीद हो गए। फोर्स शनिवार सुबह कोरोसकोडा के जंगल में सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों की बिछाई गई आईईडी को डिप्यूज करते समय अचानक जोरदार धमाका हुआ। मामला छोटेबेठिया थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि धमाका इतना तेज था कि मौके पर मौजूद जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में घायल जवानों का तुरंत रेस्क्यू किया गया,लेकिन गंभीर चोटों के कारण 3 जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल जवान परमानंद कोर्राम को बेहतर इलाज के लिए रायपुर एयरलिफ्ट गया था, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। इस घटना पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर सवाल उठाए, कहा कि नक्सलवाद के खत्म होने के राजनीतिक नारे से काम नहीं चलेगा।

बस्तर आईजी बोले...सूचना के आधार पर चल रहा था अभियान

बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी. ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि, सर्च के दौरान सुरक्षाबलों को एक नक्सली डंप भी मिला है। सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मिले इनपुट के आधार पर पिछले कुछ महीनों से लगातार आईईडी बरामदगी का अभियान चलाया जा रहा है। आज का अभियान भी उसी का हिस्सा था। इस दौरान हादसा हुआ।

भूपेश बोले...राजनीतिक नारे से काम नहीं चलेगा

इस घटना पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को समझना होगा कि नक्सलवाद के ख़त्म होने के राजनीतिक नारे से काम नहीं चलेगा। नक्सली अपने पीछे आतंक के जो अवशेष छोड़ गए हैं, उनसे मुक्ति का भी अभियान छेड़ना पड़ेगा। यह लड़ाई साझी है, लोकतंत्र विरोधी ताकतों का समूल नाश ही एकमात्र विकल्प है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा की तारीखें बदली

अब 6 जून से होंगे पेपर...

रायपुर,02 मई 2026। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा 2025 की पूर्व निर्धारित तारीखों में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। अब यह मुख्य परीक्षा 6 जून 2026 से शुरू होकर 9 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी। पहले ये परीक्षाएं 16 से 19 मई 2026 के बीच होनी थीं,जिन्हें अब प्रशासनिक कारणों से टाल दिया गया है। प्रदेश के 5 प्रमुख जिलों-सरगुजा,बिलासपुर,दुर्ग,बस्तर और रायपुर-में इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी,जिससे सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड परीक्षा की प्रारंभिक तिथि से 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें।

मौसी की बेटी से शादी अवैध : हाईकोर्ट ने कहा...प्रथा है तो साबित भी करना होगा

पत्नी को गुजारा भत्ता के आवेदन की छूट

बिलासपुर,02 मई 2026। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक अहम फैसले में कहा है कि दो सगे भाइयों या बहनों के बच्चों के बीच होने वाली शादी प्रतिषिद्ध नातेदारी के दायरे में आती है और ऐसी शादी कानूनन शून्य है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ'परंपरा' का हवाला देना काफी नहीं है,उसे पुराना,लगातार चलन में और कानून के अनुरूप साबित करना जरूरी है। हाईकोर्ट ने जांजगीर-चांपा के एक मामले में फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। दरअसल,जांजगीर-चांपा निवासी व्यक्ति की शादी 20 अप्रैल 2018 को पास के गांव की महिला से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया। इस पर पति ने फैमिली कोर्ट में आवेदन लगाकर शादी को शून्य घोषित करने की मांग की। तर्क था कि उसकी मां और पत्नी की मां सगी बहनें हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अनुसार प्रतिषिद्ध नातेदारी में शादी अवैध है। निचली अदालत ने माना था कि दोनों मौसी के बच्चे हैं, लेकिन पटेल समाज में ब्रह्म विवाह के नाम पर ऐसी शादियां प्रचलित हैं, इसलिए इसे वैध माना था।

ऑपरेशन के बाद आरक्षक की मौत

परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप प्रबंधन बोला...हार्ट अटैक से गई जान

बिलासपुर,02 मई 2026। जिले में पथरी के ऑपरेशन के बाद एक आरक्षक की मौत से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मृतक सत्यकुमार पाटले (36), जो पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर तैनात थे, की सर्जरी के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक,सत्यकुमार को 26 अप्रैल को पेट में तेज दर्द होने पर नेहरू नगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के बाद डॉक्टरों ने पथरी की पुष्टि कर ऑपरेशन की सलाह दी। 29 अप्रैल को सर्जरी की गई,जिसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन सफल बताया और मरीज की हालत सामान्य होने की बात कही। लेकिन अगले ही दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और शनिवार दोपहर उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद जब मरीज को खांसी और तकलीफ हुई,तब अस्पताल स्टाफ ने समय पर इलाज नहीं किया, जिससे हालत बिगड़ती चली गई। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करेंगे। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा था और मरीज की स्थिति सामान्य थी, लेकिन अचानक हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हुई।

प्रदेश में तापमान में गिरावट...

तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और हल्की बारिश की संभावना

रायपुर,02 मई 2026। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। आसमान में लगातार बादल छाने और सक्रिय मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक,वज्रपात और हल्की बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के कई हिस्सों में आंशिक बादल और हल्की बारिश देखने को मिली। इससे दिन के तापमान में गिरावट आई और गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलाव आने वाले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की भी संभावना है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई,जिससे मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला। इसी दौरान दुर्ग में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया,जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक रहा। वहीं अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम तापमान रहा। राजधानी रायपुर में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिनभर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। बादलों की आवाजाही और मौसम प्रणालियों के प्रभाव के चलते तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। विभाग का अनुमान है कि अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। मौसम में इस बदलाव से जहां भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिलने की संभावना है, वहीं उमस और अस्थिर मौसम लोगों को प्रभावित कर सकता है।

10 वीं में दूसरी बार फेल होने का सदमा : छात्र ने सुसाइड नोट लिखकर दी जान,बयां किया अपना दर्द...

बालोद,02 मई 2026। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 10वीं बोर्ड परीक्षा में फेल होने पर छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक राजवीर बघेल (17 साल) दूसरी बार 10 वीं की परीक्षा दे रहा था। उसे उम्मीद थी कि वह इस बार पास हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट वाले दिन एक बार फिर असफलता मिली और उसने मौत को गले लगा लिया। राजवीर का एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। घटना डौंडी थाना इलाके के बंधिया पारा की है। आत्मघाती कदम के बाद परिवार में मातम पसर गया है। जानकारी के अनुसार,राजवीर ने साल 2025 में 10 वीं की परीक्षा दी थी,जिसमें वह 6 विषयों में फेल हुआ था। खराब परिणाम के बाद परिवार के सभी सदस्यों ने उसे 10 वीं की परीक्षा पास करने के बाद काम दिलाने,दुकान खोलने जैसे अलग-अलग आश्वासन देकर उसका मनोबल बढ़ाया था। वहीं इस वर्ष फिर से परीक्षा देने गया। हालांकि बताया जा रहा है कि वह तो 5 विषयों में अनुत्तीर्ण रहा। 29 अप्रैल को परिणाम अनुकूल न आने के कारण वह गहरे मानसिक तनाव में था।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अधिकारियों को सख्त निर्देश...

कहा...नहीं चलेगी निर्माण गुणवत्ता में जरा भी लापरवाही

रायपुर,02 मई 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले के दाढ़ी नगर पंचायत क्षेत्र में हाल ही में निर्मित सीसी रोड के थोड़े ही समय में ही क्षतिग्रस्त होने की खबर को गंभीरता से लिया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही पूर्णतः अस्वीकार्य है। मुख्यमंत्री साय ने बेमेतरा की कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं से दूरभाष पर चर्चा कर पूरे प्रकरण की विस्तृत एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सीसी रोड का तकनीकी परीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए तथा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, कार्य की गुणवत्ता और पर्यवेक्षण व्यवस्था की समग्र जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि यदि जांच में गुणवत्ता में कमी, मानकों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क का त्वरित रूप से पुनर्निर्माण कर आमजन को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री साय ने यह भी निर्देश दिए कि जिले में संचालित अन्य निर्माण कार्यों की भी विशेष समीक्षा की जाए, ताकि कहीं और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की मूल जिम्मेदारी है, और इसमें किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई अनिवार्य होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सतत मॉनिटरिंग, फील्ड निरीक्षण और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के माध्यम से विकास कार्यों की विश्वसनीयता एवं टिकाऊपन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो सके। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है - जनहित के प्रत्येक कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशभर में निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित, टिकाऊ और भरोसेमंद अधोसंरचना का लाभ मिल सके।

आरटीई प्रतिपूर्ति राशि : हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को जारी किया अवमानना नोटिस...

बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट ने दायर की है अवमानना याचिका,तीन सप्ताह के भीतर देना होगा जवाब

बिलासपुर,02 मई 2026। छत्तीसगढ़ बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट ने आरटीई शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों के पढ़ाई के एवज में राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि को बढ़ाने की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 19 सितबंर 2025 को इस पर समुचित निर्णय लेने का आदेश जारी किया था। याचिकाकर्ता प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट ने न्यायालयीन आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए स्कूल शिक्षा सचिव को तीन सप्ताह की मोहलत दी है। याचिकाकर्ता बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट ने अपनी याचिका में कहा है, 14 साल से आरटीई के बच्चों की प्रतिपूर्ति राशि में किसी तरह की कोई वृद्धि राज्य सरकार ने नहीं की है। साल 2011 से राज्य सरकार द्वारा आरटीई के बच्चों की प्रतिपूर्ति राशि मात्र 7000 रुपए दी जा रही है, जो बहुत कम है। याचिका के अनुसार दूसरे राज्यों में यह राशि ज्यादा है। याचिकाकर्ता ने प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने 1 मार्च 2026 से असहयोग आंदोलन शुरू किया है। इसके तहत सरकार के किसी भी पत्र या नोटिस का जवाब नहीं दिया जा रहा है। आरटीई के तहत बच्चों को एडमिशन ना देने का निर्णय लिया है।

हाई कोर्ट ने भी प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने को कहा : छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया, बीते 14 साल से शिक्षा के अधिकार कानून के तहत दी जाने वाली राशि में राज्य सरकार द्वारा किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका विरोध प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट कर रहा है। साल 2011 में जितने भी प्राइवेट स्कूल में आरटीई के बच्चे एडमिशन लिए उन्हें कक्षा पहली से लेकर पांचवी तक 7 हजार रुपए दिए गए। छठवीं से आठवीं तक साढ़े सात हजार रुपए तय किए गए थे।

जमीन विवाद हुआ तो सीधे कलेक्टर करेंगे फैसला...कमिश्नर कोर्ट का झंझट खत्म

विष्णुदेव सरकार ने बदला सालों पुराना नियम

रायपुर,02 मई 2026। छत्तीसगढ़ में जमीन विवादों के समाधान को सरल और तेज बनाने के लिए सुशासन वाली विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 को मंजूरी देते हुए वर्षों पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जिससे अब आम लोगों और किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

कमिश्नर कोर्ट की प्रक्रिया खत्म : नए प्रावधानों के तहत अब एसडीएम स्तर पर जमीन विवाद का समाधान नहीं होने पर अपील सीधे जिला कलेक्टर के पास की जा सकेगी। पहले ऐसे मामलों में संभागीय कमिश्नर कार्यालय जाना पड़ता था, जिससे लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और समय व धन दोनों की हानि होती थी। अब यह प्रक्रिया पूरी तरह जिले के भीतर ही संपन्न होगी।

ग्रामीणों को बड़ी राहत : राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को पहले 30 से 50 किलोमीटर दूर संभाग मुख्यालयों तक जाना पड़ता था। नए कानून के लागू होने के बाद यह परेशानी समाप्त हो जाएगी। इससे समय की बचत के साथ-साथ परिवहन और कानूनी खर्चों में भी कमी आएगी।

तय समयसीमा में निपटारा

संशोधन के तहत जमीन विवाद से जुड़े मामलों का निपटारा 30 से 90 दिनों के भीतर करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे लंबित मामलों में तेजी आने की संभावना है।

अफसरों की जवाबदेही तय : सरकार ने अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की है। यदि सुनवाई में अनावश्यक देरी होती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

डिप्टी ब्रांच मैनेजर ने पति संग मिलकर 1.38 करोड़ ठगे

बिलासपुर आईसीआईसीआई बैंक से ग्राहकों की एफडी, गोल्ड लेकर भागे; नकली गहने रखे

बिलासपुर,02 मई 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आईसीआईसीआई बैंक में 1 करोड़ 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। बैंक की डिप्टी ब्रांच मैनेजर अपने पति के साथ बैंक ग्राहकों की एफडी डिपॉजिट के साथ ही गोल्ड लोन का सोना लेकर फरार हो गई है। इस घटना में कुछ और लोगों के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। गड़बड़ी सामने आने के बाद बैंक प्रबंधन ने डिप्टी ब्रांच मैनेजर को बर्खास्त कर दिया है। बैंक के ब्रांच मैनेजर की रिपोर्ट पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। मामला सिविल लाइन क्षेत्र के मंगला स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा का है। दरअसल, मंगला ब्रांच के वर्तमान ब्रांच मैनेजर अरूप पाल ने बैंक ऑडिट में गड़बड़ी पकड़ने के बाद पुलिस से शिकायत की है। उन्होंने पुलिस को बताया कि, 17 सितंबर 2025 को दैनिक बैंकिंग कार्यों के दौरान वित्तीय लेन-देन रिपोर्ट की समीक्षा की गई। जांच में पाया गया कि, रिपोर्ट का अंतिम पन्ना गायब था।

छत्तीसगढ़ में एलपीजी गैस घोटाला...प्लांट में खड़े टैंकरों से चुरा ली 1.5 करोड़ की 90 टन गैस,मैनेजर गिरफ्तार

महासमुंद,02 मई 2026। एलपीजी गैस की कालाबाजारी से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है,जिसने प्रशासन और पुलिस दोनों को चौकन्ना कर दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि सुरक्षित रख-रखाव के लिए प्लांट को सुपुर्द किए गए 6 गैस कैप्सूल वाहनों से करीब 90 मीट्रिक टन एलपीजी गैस की हेराफेरी की गई। इस गैस की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, यह पूरा खेल मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर 6 अप्रैल 2026 के बीच सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। मामले में ठाकुर पेट्रो केमिकल्स अभनपुर (उरला) के मालिक संतोष ठाकुर, डायरेक्टर सार्थक ठाकुर और प्लांट मैनेजर निखिल वैष्णव पर मिलीभगत के आरोप लगे हैं। आरोप है कि इन लोगों ने कैप्सूल वाहनों में भरी गैस को धीरे-धीरे निकालकर अलग-अलग टैंकरों के जरिए बाजार में खपा दिया। जांच के दौरान कैप्सूल वाहनों में लगे जीपीएस सिस्टम से मिली जानकारी ने पूरे घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने गतिविधियों का क्रमवार विश्लेषण किया, जिसमें सामने आया कि 31 मार्च को 2 कैप्सूल, 1 अप्रैल को 1 कैप्सूल, 3 अप्रैल को 1 कैप्सूल और 5 अप्रैल को 2 कैप्सूल से गैस निकाली गई। इस तरह कुल 6 कैप्सूल से 90 मीट्रिक टन अवैध रूप से गैस खाली की गई।

रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी

जब्त दस्तावेजों की जांच में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। रिकॉर्ड के मुताबिक अप्रैल महीने में मात्र 47 टन गैस खरीदी गई थी और शुरुआती स्टॉक भी शून्य था। इसके बावजूद 107 टन से अधिक गैस की बिक्री दर्ज दिखाई गई। खरीद और बिक्री के आंकड़ों में यह भारी अंतर साफ तौर पर चोरी और कालाबाजारी की ओर इशारा करता है।

कर्मचारियों के बयान से खुलासा

प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने यह कार्य उच्च अधिकारियों के निर्देश पर किया। गैस को पहले प्लांट के बुलेट टैंक में खाली किया जाता था और फिर निजी टैंकरों के माध्यम से अलग-अलग स्थानों पर भेज दिया जाता था।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)